सुलगता सन्नाटा
इस्लामाबाद में कूटनीति की अंत्येष्टि

लाल अंत
बंदूकों के बाद का सवाल

₹ ~~30/-~~ 20/-

सत्य सदैव

www.satyasadev.com PRGI NO : DELHIN/2017/74560 वर्ष:9, अंक:04, अप्रैल - 2026

निर्भीक, निष्पक्ष एवं निष्ठा के साथ

सत्ता संग्राम

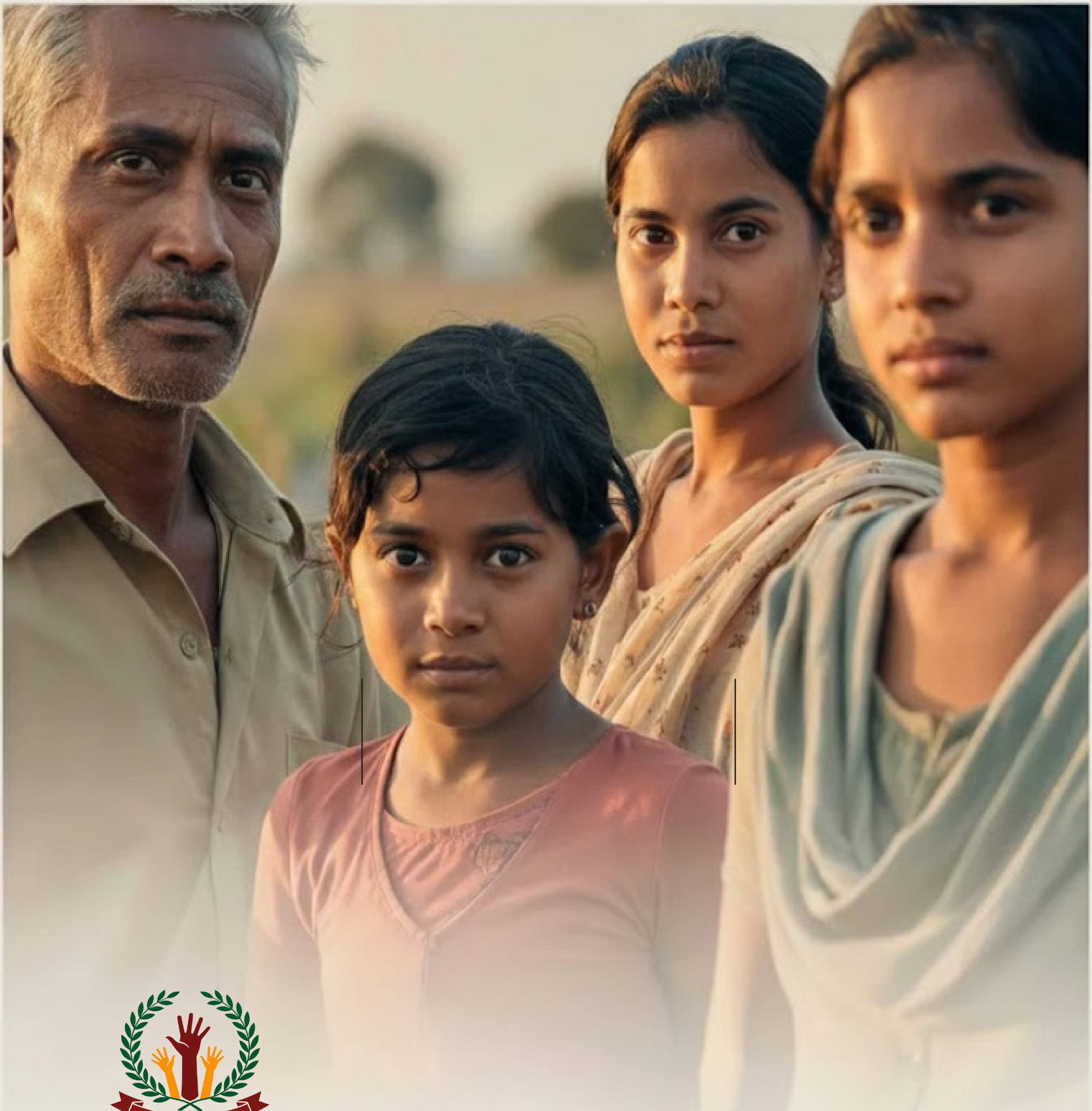

KIRTI TRUST

Compassion • Empowerment • Sustainability

EMPOWERING Lives
BUILDING Futures

CONTACT US

Head Office
M-131 ABL Work Space,
Connaught Place,
New Delhi-110001

Regd. Office
S-505, School Block,
Shakarpur, New
Delhi-110092

Project Office
Village & Post Office Kathura
District Sonipat (Haryana)
PIN- 131301

@kirtitrust
fb.com/kirtitrust
@kirti_trust

www.kirtitrust.org
info@kirtitrust.org

+91-9254-29-3293
+91-9050-29-3293

सत्य सदैव

निर्भीक, निष्पक्ष एवं निष्ठा के साथ

www.satyasadev.com PRGI NO : DELHIN/2017/74560

वर्ष:9, अंक:04, अप्रैल-2026

संपादक	राकेश कुमार
मुख्य कार्यकारी संपादक	श्रीराजेश
प्रबंध संपादक	शिव कुमार माहेश्वरी
उप संपादक	संतु दास, मनोज कुमार
सहायक उप संपादक	विशाल श्योकंद,व्यास तिवारी
विधि संपादक	एडवोकेट राखी शर्मा
कला संपादक	अमर नंदी
मुख्य संवाददाता	प्रवेश शर्मा
जनसंपर्क अधिकारी	संगीता रानी
तकनीक व साइबर हेड	अनुज कुमार सिंह
प्रसार प्रबंधक	नीतिश भारद्वाज
विपणन प्रबंधक	संदीप जिंदल
चार्टर्ड अकाउंटेंट	शिव शंकर झा

ब्यूरो

दीप्तानु दास (अगरतला)	लक्की सिंह (भोपाल)
पंकज मौर्य (लखनऊ)	संजू जोशी (देहरादून)
आशीष कुमार (जयपुर)	अजय शर्मा (श्री नगर)
अमित दास (गुवाहाटी)	नरेश आर्य (शिमला)
तेज सिंह (चंडीगढ़)	अजय कुमार(अहमदाबाद)
जितेन्द्र सिंह (रांची)	श्रीकांत (मुंबई)

संपादकीय व कॉरपोरेट कार्यालय

एस 40, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर,
नई दिल्ली-110092

ई-मेलः editor@satyasadev.com

वेबसाइटः www.satyasadev.com

दूरभाषः +91 9050 29 3293

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं। पत्रिका में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार पूर्णतः लेखकों के अपने हैं; सत्य-सदैव का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

स्वामी,प्रकाशक,मुद्रक एवं संपादक **राकेश कुमार** द्वारा मेसर्स आला प्रिंटिंग प्रेस, 3636, कटरा दिना बेग, लालकुआं दिल्ली-110006-से मुद्रित कराकर 19बी, जनता फ्लैट्स, पीरागढ़ी, नई दिल्ली 110041 से प्रकाशित

सुधि पाठकों एवं सम्मानित लेखकों से विनम्र आग्रह है कि वे अपनी प्रतिक्रियाएँ एवं प्रकाशनार्थ रचनाएँ ई-मेल द्वारा editor@satyasadev.com पर प्रेषित करें।

संपादकीय

डिजिटल नियंत्रण ढांचा
चुप्पी की ओर बढ़ता लोकतंत्र

राकेश कुमार, संपादक

आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता ने अपनी सबसे जीवंत और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे मंचों पर पाई है। यह वह क्षेत्र था जहां सीमित संसाधनों वाला एक स्वतंत्र पत्रकार भी सत्ता से सवाल कर सकता था, और नागरिक बिना किसी मध्यस्थ के अपनी बात रख सकता था। लेकिन अब प्रस्तावित डिजिटल नियंत्रण ढांचा इस स्वाभाविक स्वतंत्रता के चारों ओर एक अदृश्य परंतु सख्त घेरा खींचता हुआ दिखाई देता है। सरकार द्वारा लाए जा रहे नियमों का उद्देश्य भले ही फेक न्यूज़, डीपफेक और डिजिटल अराजकता पर नियंत्रण बताया जा रहा हो, लेकिन इसके व्यावहारिक परिणाम कहीं अधिक जटिल और चिंताजनक हो सकते हैं। 'तीन घंटे में कंटेंट हटाने' जैसे प्रावधान प्लेटफॉर्म्स को विवश करेंगे कि वे किसी भी विवादित सामग्री को बिना पर्याप्त जांच के हटा दें। यह स्थिति पत्रकारिता के उस मूल सिद्धांत के विपरीत है, जहां तथ्यों की पुष्टि और बहस का समय आवश्यक होता है। परिणामस्वरूप, प्लेटफॉर्म 'सुरक्षित' रहने के लिए आलोचनात्मक और असुविधाजनक सामग्री को भी हटाने लगेंगे।

यहीं से पत्रकारिता पर दबाव का वास्तविक तंत्र शुरू होता है। यह दबाव प्रत्यक्ष सेंसरशिप के रूप में नहीं, बल्कि एक 'चिलिंग इफेक्ट' के रूप में सामने आएगा- जहां पत्रकार स्वयं ही अपने विषयों और भाषा को सीमित करने लगेंगे। सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना, वैकल्पिक दृष्टिकोण, या संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग धीरे-धीरे कम होती जाएगी। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर ही भीतर अभिव्यक्ति की धार कुंद हो चुकी होगी।

सबसे गंभीर चिंता यह है कि ऐसे कानून ' टारगेटेड सप्रेशन' के उपकरण में बदल सकते हैं। जब 'आपत्तिजनक' या 'भ्रामक' सामग्री की परिभाषा अस्पष्ट हो, तो उसका उपयोग चयनात्मक रूप से किया जा सकता है। सत्ता के अनुकूल कथानक सुरक्षित रहेंगे, जबकि असहज सवाल उठाने वाली आवाज़ें अधिक जांच और कार्रवाई के दायरे में आएंगी। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के उस मूल तत्व को कमजोर करती है, जिसमें असहमति को स्थान दिया जाता है।

अंततः प्रश्न यह नहीं है कि कानून क्यों लाया जा रहा है, बल्कि यह है कि वह किस दिशा में समाज को ले जाएगा। यदि नियंत्रण का यह ढांचा संतुलित और पारदर्शी नहीं रहा, तो डिजिटल भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार कम और एक नियंत्रित विशेषाधिकार अधिक बनकर रह जाएगी। ●

शब्दचित्र

नियति का शंखनाद

श्रीराजेश
मुख्य कार्यकारी संपादक

यह वसंत की वेला भारत के राजनैतिक मानचित्र पर केवल ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर नहीं आई है, अपितु यह उन पांच राज्यों के भाग्य-निर्धारण का वह कालखंड है, जिसकी पदचाप दिल्ली के सत्ता-गलियारों को आंदोलित कर रही है। इस चुनावी दंगल में सभी पक्ष अपनी पूरी सामरिक क्षमता के साथ सन्नद्ध हैं। यह मात्र सत्ता का हस्तांतरण नहीं, अपितु विचारधाराओं का वह भीषण घर्षण है जो भविष्य की भारतीय राजनीति की नई दिशा और दशा तय करेगा। इन पांचों राज्यों में सर्वाधिक चर्चा, कौतूहल और विभीषिका का केंद्र 'पश्चिम बंगाल' बना हुआ है। प्रश्न वही है जो पिछले एक दशक से अनुत्तरित है - क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल अपना अजेय दुर्ग बचा पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी की केसरिया लहर इस बार गंगा के तटों पर सत्ता का नया इतिहास अंकित करेगी?

पश्चिम बंगाल की राजनीति आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां स्मृतियां और महत्वाकांक्षाएं परस्पर टकरा रही हैं। पूरब का यह राज्य भाजपा की अखिल भारतीय चुनावी विजय के रथ के सम्मुख एक सुदृढ़ प्राचीर बनकर खड़ा है। 294 विधानसभा सीटों के इस विशाल रणांगण में युद्ध अब द्वि-ध्रुवीय है - तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा। इस महासमर का सबसे रोमांचकारी पक्ष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रतिपक्ष के सेनापति शुभेंदु अधिकारी के बीच का व्यक्तिगत द्वंद्व है। भवानीपुर की गलियों से नंदीग्राम के ग्रामीण अंचलों तक, बिसात बिछ चुकी है। जहां तृणमूल 'लक्खी भंडार' की खनक और 'घोरेर मेये' (घर की बेटी) के नैरेटिव से अपनी जड़ें सींच रही है, वहीं भाजपा भ्रष्टाचार की 'चार्जशीट' और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वज्र से प्रहार कर रही है। मालदा के उग्र प्रदर्शन और निर्वाचन आयोग की एसआईआर मुहिम ने इस संघर्ष को तकनीकी जटिलता से निकालकर लोकतांत्रिक शुचिता के प्रश्न में परिवर्तित कर दिया है। ब्रह्मपुत्र की लहरों पर भी महत्वाकांक्षाओं का ज्वार है। असम में 9 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, किंतु तटों पर व्याप्त सन्नाटा अत्यंत रहस्यमयी है। यह हिमंत बिस्वा सरमा और गौरव गोगोई की प्रतिष्ठा का वह युद्ध है, जहां तर्क मौन हो जाते हैं और केवल परिणाम बोलते हैं। बिहू के उत्सव से पूर्व मतपेटियों में बंद हुई जन-आकांक्षाओं ने इस निर्वाचन को एक 'क्लासिक थ्रिलर' का स्वरूप प्रदान कर दिया है। भाजपा का सांगठनिक दुर्ग और कांग्रेस की 'असमिया उप-राष्ट्रीयता' की पुनर्स्थापना के मध्य, डिजिटल अस्त्रों और प्रत्यक्ष लाभ की योजनाओं का प्रभाव ही भावी सत्ता का मार्ग प्रशस्त करेगा।

दक्षिण की ओर दृष्टि डालें तो पुदुच्चेरी के शांत समुद्र तटों पर रसोई गैस की आंच एक अदृश्य राजनैतिक रोष बन चुकी है। 30 सीटों का यह लघु केंद्र शासित प्रदेश 'डबल इंजन' सरकार के दावों की कठोर परीक्षा ले रहा है। वहीं, तमिलनाडु में द्रविड़ अस्मिता का महासंग्राम एक अभूतपूर्व मोड़ पर खड़ा है। मुख्यमंत्री स्टालिन के 'संघीय नैरेटिव' को अभिनेता विजय की नई राजनैतिक शक्ति और आंतरिक विभीषिका से जूझती अन्नाद्रमुक से कड़ी चुनौती मिल रही है। केरलम में वामपंथ अपनी राष्ट्रीय प्रासंगिकता की अंतिम शरणस्थली को बचाने के लिए संघर्षरत है, जहां अल्पसंख्यक समीकरणों का ध्रुवीकरण और भाजपा का बढ़ता प्रभाव पारंपरिक राजनैतिक धुरी को विस्थापित करने की सामर्थ्य रखता है।

पश्चिम बंगाल के गंगा-तटों से लेकर तमिलनाडु के हिंद महासागर तक, क्षेत्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का यह घर्षण नवीन भारत का राजनैतिक डीएनए गढ़ रहा है। कल्याणकारी योजनाओं की खनक और सांस्कृतिक गौरव के स्वर तय करेंगे कि आगामी दशकों में देश के लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा क्या होगी।

4 मई 2026 की भोर जब नियति पिटारा खोलेगी, तो राख के नीचे से जो नई राजनैतिक व्यवस्था उभरेगी, वह भारत के संघीय ढांचे और सत्ता-संतुलन की नई परिभाषा होगी। पश्चिम बंगाल की अस्मिता से लेकर केरलम के सिद्धांतों तक, यह निर्वाचन केवल मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक वैचारिक 'ब्लूप्रिंट' भी तैयार करेगा। यह युद्धों का अंत नहीं, अपितु एक नए भारत की पदचाप है, जहां पहचानें अब आसमान से नहीं, बल्कि मिट्टी से तय होंगी।

वसंत की बयार इस बार केवल प्रकृति का श्रृंगार नहीं, अपितु उन पांच राज्यों के भाग्य-निर्धारण की प्रस्तावना है, जिसकी गूंज इंद्रप्रस्थ के सिंहासन को स्पंदित कर रही है। यह मात्र निर्वाचन नहीं, अपितु भारतीय राजनीति के भविष्य का निर्णायक वैचारिक प्रतिवेदन है।

इस अंक में खास...

आवरण कथा

14 सत्ता संग्राम

04

सुलगता सन्नाटा

इस्लामाबाद की मेज पर बिखरी कूटनीतिक रिक्तता ने मध्य-पूर्व के क्षितिज पर पुनः युद्ध के बादलों को सघन कर दिया है। अमेरिका-ईरान वार्ता की यह विफलता भारत के लिए केवल एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की अंतिम और निर्णायक कसौटी है।

08

रसोई का संकट

पश्चिम एशिया के रक्तवर्ण क्षितिज से उठी युद्ध की लपटों ने दिल्ली की रसोइयों को शीतलता और धुएं के आगोश में धकेल दिया है। आधुनिकता का उज्ज्वल स्वप्न आज हॉर्मुज जलडमरूमध्य के सामरिक अवरोधों और खाली सिलेंडरों की लंबी कतारों के बीच दम तोड़ रहा है।

लाल अंत

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई सम्मेलन केवल तकनीकी आयोजन नहीं था, बल्कि उस बदलते वैश्विक समीकरण का संकेत था जिसमें भारत उपभोक्ता नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य का निर्माता बनने की आकांक्षा के साथ विश्व मंच पर उभर रहा है।

24

रॉकेट फोर्सः युद्ध का नया व्याकरण 26

डिजिटल विद्रुपता... 30

थोरियम का शंखनाद 32

बिहार में नया 'सम्राट' 34

आकाश की विवशता 36

अंबर के आलिंगन का महाभ्यास.....40

44

कृति का गेम चेंज!

हीरोइन या 'लेडी बॉस'

इस्लामाबाद में कूटनीति की अंत्येष्टि

सुलगता सन्नाटा

इस्लामाबाद की मेज पर बिखरी कूटनीतिक रिक्तता ने मध्य-पूर्व के क्षितिज पर पुनः युद्ध के बादलों को सघन कर दिया है। अमेरिका-ईरान वार्ता की यह विफलता भारत के लिए केवल एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की अंतिम और निर्णायक कसौटी है।

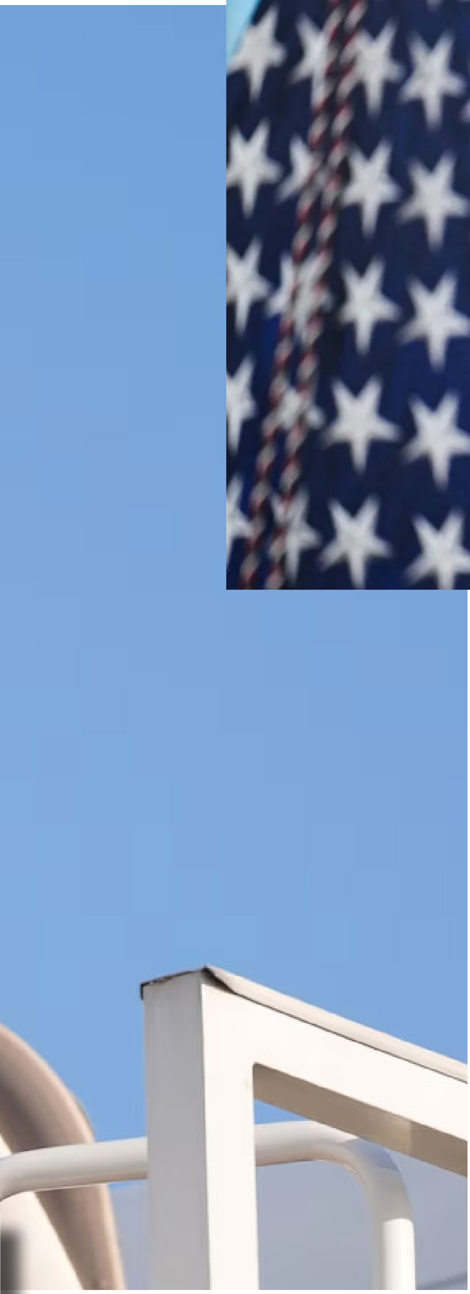

28 फरवरी को प्रारंभ हुई वह विभीषिका, जिसने समूचे पश्चिम एशिया को बारूद की गंध और रक्तवर्ण आकाश में विलीन कर दिया था, आज एक अत्यंत भयावह मोड़ पर खड़ी है। 12 अप्रैल इतिहास के पन्नों में उस कूटनीतिक विफलता के रूप में अंकित की जाएगी, जिसने वैश्विक शांति की आशाओं को इस्लामाबाद के गलियारों में दफन कर दिया। पाकिस्तान की मध्यस्थता में आयोजित अमेरिका और ईरान के बीच की 'अस्थायी शांति वार्ता' बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई है। जिसे दुनिया एक 'रणनीतिक विराम' समझ रही थी, वह अंततः महायुद्ध के अगले और अधिक विनाशकारी चरण की प्रस्तावना सिद्ध हुई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बिजली और ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों को रोकने का एकतरफा ऐलान और उसके बाद वार्ता की मेज का खाली रह जाना, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की एक ऐसी पराजय है, जिसकी गूँज अब तेल के कुओं से लेकर परमाणु संयंत्रों तक सुनाई देगी।

ट्रम्प का 'ट्रुथ' और बाजार का उन्माद

डोनाल्ड ट्रम्प की कूटनीति अब अंतरराष्ट्रीय संधियों की गरिमा के बजाय उनके 'ट्रूथ सोशल' के टूटे-फूटे वाक्यांशों और हिज्जों की त्रुटियों में प्रतिध्वनित होती है। उनकी अजब-गजब फितरत ने समूचे विश्व की धड़कनों को अनिश्चित बना दिया है। जब ट्रम्प ने पोस्ट किया कि 'ईरान के एक सम्मानित नेता के साथ खुशनुमा बातचीत जारी है,' तो अमेरिकी शेयर बाजार ने 20 खरब डॉलर की लंबी छलांग लगाई। किंतु, यह उल्लास क्षणभंगुर रहा।

जैसे ही ईरान की मजलिस के अध्यक्ष मुहम्मद बगेर घालीबाफ ने इसे वाशिंगटन की 'छटपटाहट' और 'फर्जी खबर' बताकर खारिज किया, बाजार 10 खरब डॉलर के गहरे गर्त में जा गिरा। यह उतार-चढ़ाव केवल पूंजी का क्षरण नहीं, बल्कि उस वैश्विक घबराहट का प्रतिबिंब है जो दिखाती है कि एक महाशक्ति की साख अब कितनी जर्जर हो चुकी है। बाजार इस आशंका से अस्थिर हैं कि हॉर्मुज के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति में होने वाला व्यवधान अब दीर्घकालिक होने वाला है।

राकेश कुमार

इस्लामाबाद की बिसात: 10 बनाम 15 अंक

वार्ता की विफलता का मुख्य कारण उन 'अंकों' में निहित था, जो दोनों पक्षों ने मेज पर रखे थे। ट्रम्प का 15-सूत्रीय प्रस्ताव जहां ईरान के पूर्ण निरस्त्रीकरण, यूरेनियम संवर्धन पर स्थायी रोक और बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विसर्जन की मांग कर रहा था, वहीं ईरान का 10-सूत्रीय 'कार्यकारी आधार' संप्रभुता के नए समीकरण गढ़ रहा था।

तेहरान की मांगें किसी पराजित राष्ट्र की नहीं, बल्कि एक 'प्रतिरोध की धुरी' की हुंकार थीं - अक्रामकता पर पूर्ण विराम, हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर स्थायी ईरानी नियंत्रण, और लेबनान में जारी युद्ध का अंत। ईरान द्वारा हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 'पारगमन शुल्क' वसूलने की मांग ने वाशिंगटन के उस वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती दी है, जिसे उसने दशकों से अक्षुण्ण रखा था।

आर्थिक महाप्रलय: तेल, यूरिया और 'मागा' का संकट

जंग की आंच अब हॉर्मुज से निकलकर अमेरिका के आयोवा और भारत के सूरत तक पहुंच चुकी है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें, जो जंग से पूर्व 65 डॉलर के आसपास थीं, अब 120 डॉलर के पार जा चुकी हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि तनाव और बढ़ा, तो यह आंकड़ा 200 डॉलर प्रति बैरल के उस विनाशकारी स्तर को छू लेगा, जहां से वैश्विक मंदी का मार्ग प्रशस्त होता है।

सबसे भयावह संकट 'युद्ध की थाली' में दिख रहा है। प्राकृतिक गैस की ऊंची कीमतों ने यूरिया के उत्पादन को संकट में डाल दिया है। अमेरिका का वह किसान, जो ट्रम्प के 'मागा' आंदोलन का मेरुदंड है, आज आयोवा के खेतों में खाद के नाइट्रोजन संकट से जूझ रहा है। ट्रम्प के लिए यह युद्ध अब चुनावी विवशता बन चुका है। यदि खाद का संकट अनाज के अकाल में बदला, तो नवंबर के मध्यावधि चुनाव उनके लिए 'राजनैतिक अंत्येष्टि' सिद्ध हो सकते हैं।

भारत के लिए कूटनीतिक अग्निपरीक्षा

भारत के लिए इस वार्ता की विफलता के प्रभाव दोहरे और अत्यंत जटिल हैं। एक ओर ऊर्जा सुरक्षा का संकट है, जहां भारत अपनी तेल जरूरतों का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। आपूर्ति बाधित होने से घरेलू बाजार में महंगाई का अनियंत्रित होना सुनिश्चित है। दूसरी ओर, चाबहार बंदरगाह परियोजना, जो मध्य एशिया तक पहुंचने का भारत का गेटवे है, अब कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के साये में पुनः अधर में लटक गई है।

किंतु, इस विफलता ने भारत के लिए कूटनीतिक अवसर के द्वार भी खोले हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता विफल होने के बाद अब वैश्विक समुदाय की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हैं। भारत के संबंध वाशिंगटन और तेहरान - दोनों के साथ ऐतिहासिक और संतुलित हैं। वाशिंगटन को अब यह एहसास हो सकता है कि पाकिस्तान के बजाय भारत एक अधिक विश्वसनीय और प्रभावी मध्यस्थ सिद्ध हो सकता है। यह स्थिति भारत को अमेरिका के साथ व्यापारिक और रक्षा सौदों के लिए एक उच्च 'बार्गेनिंग पावर' प्रदान करती है।

सैन्य मिथकों का विखंडन और परमाणु प्रसार

इस युद्ध ने उस मिथक को ध्वस्त कर दिया है कि पश्चिमी तकनीक को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। पेंटागन की वह पुष्टि, जिसमें ईरान द्वारा एफ-35 और एफ-16 विमानों को मार गिराने की बात कही गई, आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा 'शॉक' है। इजराइल के अति-गोपनीय परमाणु संयंत्र वाले डिमोन और

अराद शहरों में ईरानी मिसाइलों की तबाही ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी-इजराइली सुरक्षा कवच अब अभेद्य नहीं रहा।

वार्ता विफल होने का अर्थ यह भी है कि ईरान परमाणु समझौता (जेसीपीओए) अब इतिहास बन चुका है। तेहरान अब यूरेनियम संवर्धन की गति को बढ़ा सकता है, जिससे क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा है। यह स्थिति सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों को अस्तित्वगत सुरक्षा के लिए और अधिक आक्रामक कदम उठाने पर विवश करेगी।

पेट्रो-युआन और भू-राजनैतिक विस्थापन

सबसे घातक प्रहार डॉलर के साम्राज्य पर हुआ है। ईरान ने शर्त रखी है कि तेल और गैस का सौदा अब 'पेट्रो-युआन' में होगा। आठ राष्ट्रों की रजामंदी डॉलर के वर्चस्व के ताबूत में आखिरी कील की तरह है। ट्रम्प द्वारा उन देशों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी, जो ईरान को हथियार दे रहे हैं, असल में इसी 'वित्तीय विद्रोह' को दबाने की एक निष्फल कोशिश है। 2026 का ईरान अब रूस और चीन की जुगलबंदी के साथ खड़ा है, जो 'पेट्रो-डॉलर' के विकल्प को वास्तविकता बना रहे हैं।

लेबनान: वह शांति जो वहां नहीं है

संधि-विराम के विज्ञापनों के बीच लेबनान की हकीकत हृदयविदारक है। बेका घाटी के शमेस्तर गांव में एक जनाजे पर इजराइली बमबारी और टायर शहर के केंद्र में गिरे मिसाइल चीख-चीख कर कह रहे हैं कि 'यहां कोई सीजफायर नहीं है।' इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका ईरान के साथ समझौता लेबनान के हिज्बुल्लाह पर लागू नहीं होता। यह 'चयनात्मक शांति' दिखाती है कि युद्ध का व्याकरण अब रणनीतिक लक्ष्यों के आधार पर लिखा जा रहा है।

राख के नीचे दबी नई दुनिया

इस्लामाबाद वार्ता की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य-पूर्व का मुद्दा पाकिस्तान जैसे देशों की मध्यस्थता से सुलझने वाला नहीं है। खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए रवाना हुए 3,000 अमेरिकी मैरीन्स की पदचाप और वार्ता की मेज पर बिखरा सन्नाटा, एक बड़े वैश्विक संकट की ओर संकेत कर रहे हैं।

भारत के लिए यह समय 'सतर्कता के साथ अवसर' का है। उसे अब अपनी 'पश्चिम एशिया नीति' को और अधिक सक्रिय करना होगा। मार्च 2026 की यह युद्ध-ज्वाला जब शांत होगी, तो राख के नीचे से जो नई दुनिया निकलेगी, उसमें न तो अमेरिका की वैसी अजेयता होगी और न ही डॉलर का वैसा एकछत्र राज। दुनिया ने देख लिया है कि जंग दो की हो, तबाही सबकी होती है। ●

रसोई का संकट

खाली सिलेंडर, लंबी कतारें

पश्चिम एशिया के रक्तवर्ण क्षितिज से उठी युद्ध की लपटों ने दिल्ली की रसोइयों को शीतलता और धुएं के आगोश में धकेल दिया है। आधुनिकता का उज्ज्वल स्वप्न आज हॉर्मुज जलडमरूमध्य के सामरिक अवरोधों और खाली सिलेंडरों की लंबी कतारों के बीच दम तोड़ रहा है।

सत्य सदैव ब्यूरो

दिल्ली के कई मोहल्लों में सूर्योदय की पहली किरण फूटने से बहुत पहले ही कतारें अपनी जड़ें जमा लेती हैं। भोर के चार बजते-बजते, जब शहर का एक बड़ा हिस्सा गहरी निद्रा में होता है, गैस वितरकों के द्वारों पर एक भिन्न प्रकार का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। इस कतार में कोई भेद नहीं है - दिहाड़ी मजदूर, गृहणियां, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे रेस्तरां संचालक, सभी की आंखों में एक ही व्याकुलता हैः एक सिलेंडर की प्राप्ति। इनमें से अधिकांश लोग दोपहर तक खाली हाथ, थके हुए कदमों के साथ वापस लौट जाते हैं। यह केवल ईंधन की कमी नहीं है, बल्कि एक महानगरीय सभ्यता के विश्वास का टूटना है।

रसोई गैस की अनुपस्थिति में घरों के भीतर जो दृश्य उभर रहे हैं, वे समय के चक्र को पीछे घुमाने जैसा अनुभव कराते हैं। दिल्ली की आधुनिक कॉलोनियों के पड़ोस में स्थित बस्तियों में परिवार संसाधनों को एकत्रित कर सामूहिक रसोई का सहारा ले रहे हैं। कहीं कोयले की अंगीठी सुलग रही है, तो कहीं जलाऊ लकड़ी और उपलों (गोबर) का उपयोग कर भोजन पकाने का आदिम प्रयास किया जा रहा है। दो वक्त की रोटी सुनिश्चित करना अचानक एक थका देने वाला दैनिक संग्राम बन चुका है।

आंकड़ों का शिखर और यथार्थ की ढलान

राजधानी के कुछ हिस्सों में उभर रहे ये दृश्य भारत की ऊर्जा नीति के पिछले एक दशक के पथ के बिल्कुल विपरीत खड़े हैं। देश में आज घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 32.83 करोड़ से अधिक है, जो 2014 के 14.52 करोड़ से एक लंबी छलांग थी। यह स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक व्यापक पहुंच का एक गौरवशाली अध्याय था। किंतु, वर्तमान व्यवधान ने इस उपलब्धि पर अनिश्चितता का कुहासा फैला दिया है।

इस संकट की जड़ें पश्चिम एशिया के उस ज्वालामुखी में निहित हैं, जो 28 फरवरी 2026 को फटा था। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए व्यापक हमलों ने तेहरान को जवाबी कार्रवाई के लिए विवश किया, जिसके परिणामस्वरूप

फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। ईरान ने इजराइल और खाड़ी के अमेरिकी समर्थक देशों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे वाणिज्यिक नौवहन के मन में गहरा भय व्याप्त हो गया है।

हॉर्मुज: वैश्विक अर्थव्यवस्था की महाधमनी

इस व्यवधान के केंद्र में 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' है - ईरान और ओमान के बीच का वह संकरा समुद्री मार्ग जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। विश्व की लगभग पांचवां हिस्सा तेल और गैस की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। भारत के लिए यह जलमार्ग किसी 'महाधमनी' से कम नहीं है। देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40-50 प्रतिशत, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आधा हिस्सा और एलपीजी खेप का एक बड़ा भाग इसी संकरे मार्ग से होकर गुजरता है।

नई दिल्ली जैसे शहरों में रसोई गैस की आपूर्ति में अचानक आई कमी इसी सामरिक जकड़न का परिणाम है। घरों में 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीद) बढ़ गई है, जबकि रेस्तरां और सड़क किनारे भोजन बेचने वाले, जो पूरी तरह से 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडरों पर निर्भर हैं, सबसे भीषण मार झेल रहे हैं। कई भोजनालयों ने या तो अस्थायी रूप से शटर गिरा दिए हैं या अपने परिचालन को न्यूनतम स्तर पर ले आए हैं। हॉस्टलों और कैंटीनों में भोजन की राशनिंग शुरू हो गई है।

नदिया और मिट्टी के चूल्हे की त्रासदी

ओखला फेज 2 की एक तंग और भीड़भाड़ वाली झुग्गी बस्ती में, जहां छोटे-छोटे घर एक-दूसरे से सटे हुए हैं, ढांचों के बीच का एक खुला टुकड़ा 'साझा रसोई' में तब्दील हो गया है। यहाँ पांच परिवार - हिंदू और मुस्लिम दोनों - एक ही मिट्टी के चूल्हे के चारों ओर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जमीन कालिख से काली पड़ चुकी है, दीवारें धुएं से धूसर हैं और हवा में वह सघन धुआं व्याप्त है जो आग बुझने के काफी बाद तक फेफड़ों में चुभता रहता है।

राजस्थान की मूल निवासी नदिया चूल्हे के पास बैठी अपनी सब्जी चला रही है। दो कमरों के एक कच्चे-पक्के मकान में रहने वाली नदिया बीच-बीच में अपनी आंखें पोंछती है - कभी धुएं के कारण, तो कभी थकान से। वह कहती है, 'पिछले चार-पांच दिनों से हम इसी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। न जगह है, न लकड़ी आसानी से मिलती है। धुएं ने जीना मुहाल कर दिया है, पर विकल्प क्या है? सिलेंडर बुक किए 10 दिन हो गए, अब तक नहीं आया।' यहाँ के अधिकांश निवासी दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी आय अनिश्चित है। पास खड़ी एक अन्य महिला कहती है, 'कभी काम मिलता है, कभी नहीं। ऐसे में दो-तीन हजार रुपये कालाबाजारी में देना हमारे बस की बात नहीं है।'

अदृश्य कोलेटरल डैमेजः रिहाना और पपिया की व्यथा

यह संकट केवल चूल्हे तक सीमित नहीं है, इसके सामाजिक दुष्प्रभाव गहरे हैं। जय हिंद कैंप में महिलाएं सुबह 6 बजे से लाइन में लगती हैं और दोपहर 2 बजे तक प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें अगले दिन आने को कह दिया जाता है। पपिया नामक निवासी ने बताया कि उन्हें दो दिनों तक बाहर के भोजन पर निर्भर रहना पड़ा, जो उनके लिए 'आर्थिक रूप से वहनीय' नहीं था।

रिहाना, जो वसंत कुंज की एक पॉश गेटेड सोसायटी में घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करती है, कहती है कि इन लंबी कतारों ने उसकी नौकरी को खतरे में डाल दिया है। 'मेरी मालकिन कहती है कि एक घंटे से ज्यादा मत लगाओ। पर एक घंटे में कैसे होगा? आधा दिन लाइन में निकल जाता है, फिर घर आकर सारा काम भी करना पड़ता है।' मध्यम वर्ग की एक महिला के शब्द इस वर्ग की नियति को स्पष्ट करते हैं: 'हम गरीब हैं, इसलिए घंटों कतार में खड़े रहना हमारी वास्तविकता है। जब भी संकट आता है, हम जैसे लोग ही सबसे पहले शिकार होते हैं।'

आयात पर निर्भरता और मूल्य वृद्धि का चक्र

भारत की ऊर्जा सुरक्षा का ढांचा यद्यपि सुदृढ़ है, किंतु आयात पर उसकी निर्भरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी

> **पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएक) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन दशकों में भारत की एलपीजी खपत में छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है – 1998–99 के 446 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2025–26 में 2,754 हजार मीट्रिक टन।**

रिफाइनरियां देश की एलपीजी मांग का केवल 40 प्रतिशत ही पूरा कर पाती हैं। शेष 60 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों से आयात किया जाता है।

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएक) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन दशकों में भारत की एलपीजी खपत में छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है - 1998-99 के 446 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 2,754 हजार मीट्रिक टन। इस अवधि में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी 15,000 किमी से बढ़कर 25,000 किमी हो गया। उद्देश्य स्पष्ट थाः करोड़ों घरों को पारंपरिक ईंधन से मुक्त कर एक आधुनिक ऊर्जा प्रणाली में लाना। किंतु, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 'सऊदी अनुबंध मूल्य' में हुई 63 प्रतिशत की वृद्धि ने इस तंत्र पर भारी दबाव डाल दिया है। वर्तमान में दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 803 रुपये है, जबकि उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए यह प्रभावी रूप से 503 रुपये है। किंतु कालाबाजारी ने इन कीमतों को अप्रासंगिक बना दिया है।

गोविंदपुरी में रहने वाले संजय सिंह पिछले 25 वर्षों से समोसे, लिट्टी और आलू चाट की रेहड़ी चला रहे हैं। महज पांच रुपये प्रति आइटम बेचने वाले संजय दिन भर में बमुश्किल 200-400 रुपये बचा पाते हैं, जिससे उनका सात-आठ सदस्यों का परिवार पलता है। एलपीजी की कमी ने उनके चूल्हे और धंधे, दोनों को ठंडा कर दिया है। 'पिछले आठ दिनों से रेहड़ी बंद है। घरेलू सिलेंडर भी छह दिन बाद मिला। मेरी बेटी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लाइन में लगी, तब जाकर एक पर्ची मिली।' संजय ने कालाबाजारी में 400-500 रुपये प्रति किलो गैस भरने की कोशिश की, पर वह भी अब संभव नहीं है। आय का स्रोत बंद होने और बेटे के एक्सीडेंट के कारण बढ़ते खर्चों ने उन्हें गांव लौटने पर विचार करने को मजबूर कर दिया है।

ऐसी ही कहानी 'गुप्त जी' की है, जो छोले-पूरी का स्टाल लगाते हैं। गैस की कमी से उनका कारोबार आधा रह गया है। ऑनलाइन बुकिंग का कोई जवाब नहीं मिल रहा। स्टाल चलाने के लिए उन्होंने घर का सिलेंडर उपयोग किया, जिससे बच्चों को उनकी दादी के घर भेजना पड़ा। 'स्टाल पर पांच कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? स्थिति यही रही तो दुकान पूरी तरह बंद करनी होगी।'

शिक्षा के केंद्रों में पसरता सन्नाटा

एलपीजी संकट ने गोविंदपुरी और ओखला जैसे क्षेत्रों में रहने वाले उन हजारों छात्रों को भी प्रभावित किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के पीजी और हॉस्टल, जो छात्रों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, अब भोजन की थाली छोटी कर रहे हैं। रोटियों की संख्या कम हो गई है, सब्जियों की विविधता लुप्त हो गई है।

ओखला फेज 2 के एक पीजी में कर्मचारी अब गोबर के उपलों और लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। ओखला के एक पीजी केयरटेकर आलम बताते हैं, 'हम सुबह 3 बजे उठकर लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं ताकि 7 बजे तक नाश्ता तैयार हो सके। पूरा हॉल धुएं से भर जाता है, पर बच्चों को भूखा नहीं रख सकते।' फास्ट फूड, जो कभी सप्ताहांत का आनंद था, अब एक 'विशेषाधिकार' बन चुका है।

सरकारी तंत्र और जनता का संशय

बढ़ती चिंता के बीच, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय का दावा है कि गैस

की पर्याप्त उपलब्धता है और समस्या 'जमाखोरी' के कारण उत्पन्न हुई है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि लोग डर के मारे सिलेंडर जमा कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम कमी पैदा हुई है।

किंतु जय हिंद कैंप में कतार में खड़े अनवर हुसैन जैसे लोगों के लिए ये स्पष्टीकरण किसी काम के नहीं हैं। 'अगर उपलब्धता समस्या नहीं है, तो फिर इतनी भ्रम की स्थिति और इतनी लंबी लाइनें क्यों हैं? पहले नोटबंदी की कतारें और अब गैस की - इस सरकार के साथ समस्याएं कभी खत्म नहीं होतीं।'

राजनयिक संतुलन और भविष्य की चुनौती

भारत इस समय पश्चिम एशिया में एक अत्यंत नाजुक राजनयिक संतुलन बना रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तेहरान के साथ निरंतर बातचीत की पुष्टि की है। भारत के इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और अमेरिका के साथ बढ़ता रणनीतिक सहयोग है, किंतु ईरान के साथ उसके पुराने राजनैतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं। नई दिल्ली के लिए खाड़ी में वाणिज्यिक नौवहन मार्गों की सुरक्षा केवल एक भू-राजनीतिक चिंता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आर्थिक आवश्यकता है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तेहरान के साथ निरंतर बातचीत की पुष्टि की है। भारत के इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और अमेरिका के साथ बढ़ता रणनीतिक सहयोग है, किंतु ईरान के साथ उसके पुराने राजनैतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं।

धुएं से घिरा भविष्य

मार्च 2026 का यह एलपीजी संकट केवल एक ईंधन की कमी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि हमारी 'स्वच्छ ऊर्जा' का भविष्य कितनी असुरक्षित धागों से बंधा है। जब तक हॉर्मुज की धमनियां युद्ध के अवरोधों से मुक्त नहीं होतीं, तब तक गोविंदपुरी की शीला को बुखार में लकड़ी पर खाना बनाना पड़ेगा और संजय सिंह की रेहड़ी बंद रहेगी।

आंकड़ों और योजनाओं के भव्य महलों के नीचे, आज भारत की एक बड़ी आबादी धुएं और कालिख के उस अतीत में लौटने को विवश है, जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। यह संकट सिद्ध करता है कि 21वीं सदी में युद्ध का भूगोल भले ही सात समंदर पार हो, उसकी आंच सीधे गरीब की थाली तक पहुंचती है। भारत को अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए केवल कूटनीति नहीं, बल्कि सामरिक विकल्पों और घरेलू उत्पादन के सुदृढ़ीकरण की ओर देखना होगा। अन्यथा, भविष्य की हर मिसाइल का धमाका हमारे रसोई घरों में शांति का अंत करता रहेगा। ●

सत्य सदैव

से जुड़ें

विचारों का सच्चा संगम

सत्य सदैव वह मंच है जहां विविध दृष्टिकोण, अनुभव और विचार एक साथ मिलते हैं। यह उन जिज्ञासु और जागरूक पाठकों का मंच है जो अपने समय के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्नों को गहराई से समझना चाहते हैं। हमारा प्रयास केवल समाचार देना नहीं, बल्कि विचारों का ऐसा संवाद स्थापित करना है जहां मतभेद के बावजूद सार्थक चर्चा हो सके। सत्य सदैव अपने पाठकों को एक ऐसा बौद्धिक मंच प्रदान करता है जहां खुली सोच, तर्कपूर्ण विमर्श और परस्पर सम्मान के साथ हम अपने समाज और दुनिया को समझने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

सत्य सदैव को सब्सक्राइब करें

और बनें उस समुदाय का हिस्सा जो सत्य, संवाद और विचार की शक्ति में विश्वास रखता है।

केवल ₹ 30 प्रति अंक

अभी ऑर्डर करें: satyasadev.com

satyasadev.com का असीमित एक्सेस	विज्ञापन-मुक्त साइट ब्राउज़ करें	विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर उपलब्ध	शीघ्र ही YouTube पर भी होगी हमारी मौजूदगी

सब्सक्रिप्शन का वार्षिक ₹ 300। यह ऑफर केवल नए सब्सक्राइबर्स के लिए है।

श्रीराजेश

भारत की राजनीतिक धरती पर पांच राज्यों का चुनावी संग्राम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विचारधाराओं के निर्णायक टकराव का मंच बन चुका है। यह मुकाबला आने वाले वर्षों में देश की दिशा, दशा और लोकतांत्रिक संतुलन को परिभाषित करेगा।

सत्ता संग्राम

यह वसंत वेला भारत के राजनैतिक मानचित्र पर केवल ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर नहीं आई है, बल्कि यह उन पांच राज्यों के भाग्य निर्धारण का कालखंड है, जिनकी गूंज दिल्ली के सत्ता-गलियारों को आंदोलित करने वाली है। इस चुनावी दंगल में सभी पक्ष अपनी पूरी सामरिक क्षमता के साथ ताल ठोक रहे हैं। यह मात्र सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि विचारधाराओं का वह घर्षण है जो भविष्य की भारतीय राजनीति की नई दिशा और दशा तय करेगा। इन पांचों राज्यों में सर्वाधिक चर्चा, कौतूहल और विभीषिका का केंद्र 'पश्चिम बंगाल' बना हुआ है। प्रश्न वही है जो पिछले एक दशक से अनुत्तरित है - क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल अपना अजेय दुर्ग बचा पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी की केसरिया लहर इस बार गंगा के तटों पर सत्ता का नया इतिहास अंकित करेगी?

पश्चिम बंगाल: गढ़ बचाने और भेदने के तीखे तेवर

पश्चिम बंगाल की राजनीति आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां स्मृतियां और महत्वाकांक्षाएं परस्पर टकरा रही हैं। पूरब का यह राज्य भाजपा की अखिल भारतीय चुनावी विजय के रथ के सामने एक सुदृढ़ और दुर्गम प्राचीर बनकर खड़ा है। वर्ष 2011 में जब तीन दशकों के वामपंथी शासन का अवसान हुआ और ममता बनर्जी ने सत्ता की बागडोर संभाली, तब से बंगाल का राजनैतिक परिदृश्य आमूल-चूल परिवर्तित हो चुका है। 2011 में जिस भाजपा का अस्तित्व शून्य सीटों पर सिमटा था, उसका आज मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरना किसी राजनैतिक चमत्कार से कम नहीं है। इस परिवर्तन ने बंगाल के पारंपरिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है।

कभी राज्य की नियति तय करने वाली वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस आज अपने अस्तित्व और प्रासंगिक होने की अंतिम लड़ाई लड़ रही हैं। अब यह युद्ध द्वि-ध्रुवीय है - तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा।

294 विधानसभा सीटों के इस विशाल रणांगण में दोनों पक्ष बहुमत के जादुई आंकड़े (148 सीटें) को पार करने के लिए व्याकुल हैं। 2021 का चुनाव इतिहास के पन्नों में तृणमूल की उस अभूतपूर्व विजय के लिए दर्ज है, जहां उसने 215 सीटें जीतकर अपनी जड़ें पुनः गहरी कर ली थीं। उस समय भाजपा 77 सीटों पर थम गई थी, जबकि कांग्रेस और माकपा का खाता तक न खुल पाना भारतीय संसदीय इतिहास की एक विद्रूप घटना थी। किंतु 2026 का परिदृश्य 2016 की तुलना में पूर्णतः भिन्न है। 2016 में जब तृणमूल के पास 211 सीटें थीं, तब कांग्रेस और माकपा क्रमशः

पिछले कुछ महीनों से ममता बनर्जी निर्वाचन आयोग की 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (एसआईआर) मुहिम के विरुद्ध एक प्रचंड प्रतिरोधी स्वर बनकर उभरी हैं। आयोग पर उनके निरंतर प्रहारों और इस मुहिम को लेकर जताई गई चिंताओं ने राज्य के जनमानस में एक संशय की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

44 और 26 सीटों के साथ एक प्रभावी विपक्ष थे, और भाजपा मात्र 3 सीटों के साथ हाशिये पर थी। आज का यथार्थ यह है कि विपक्ष का अर्थ केवल भाजपा है।

इस महासमर का सबसे रोमांचकारी पक्ष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच का व्यक्तिगत और राजनैतिक द्वंद्व है। शुभेंदु अधिकारी इस बार रणनीतिक आक्रामकता का परिचय देते हुए दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वे अपनी परंपरागत नंदीग्राम की सीट के साथ-साथ कोलकाता के हृदय स्थल 'भवानीपुर' में ममता बनर्जी को उनके घर में चुनौती दे रहे हैं। यह दृश्य 2021 का विलोम है, जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम जाकर शुभेंदु को ललकारा था और एक अत्यंत सूक्ष्म अंतर से पराजित हुई थीं।

किंतु यह लड़ाई केवल दो चेहरों तक सीमित नहीं है। तृणमूल की ओर से फिरहाद हकीम, ब्रात्य बसु, चंद्रिमा भट्टाचार्य, अरूप राय, सुजीत बोस और शशि पांजा जैसे अनुभवी योद्धा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक लाहिड़ी और नीरज तमांग जिम्बा जैसे प्रखर वक्ताओं और रणनीतिकारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाजपा द्वारा 40 स्टार प्रचारकों को भी चुनावी रण में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। पर्दे के पीछे तृणमूल के महासचिव अभिषेक बनर्जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य संगठन की गोटियाँ सेट करने में अहोरात्र संलग्न हैं।

पिछले कुछ महीनों से ममता बनर्जी निर्वाचन आयोग की 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (एसआईआर) मुहिम के विरुद्ध एक प्रचंड प्रतिरोधी स्वर बनकर उभरी हैं। आयोग पर उनके निरंतर प्रहारों और इस मुहिम को लेकर जताई गई चिंताओं ने राज्य के जनमानस में एक संशय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। विषय की गंभीरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलीलें रखने पहुंचीं। न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात भी एसआईआर की स्थिति एक पहेली बनी हुई है। लगभग 90 लाख

मतदाता 'संदिग्ध सूची' के अंधकार में हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर बीते दिनों मालदा में जिस प्रकार न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया और उग्र प्रदर्शन किये गये तत्पश्चात पुलिस की कार्रवाई ने बंगाल चुनाव की दिशा बदली है। यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं, बल्कि बंगाल की अस्मिता और लोकतांत्रिक शुचिता का प्रश्न बन चुका है।

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा के उपरांत जिस तीव्र गति से मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस कमिश्नर सहित 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया, उसे ममता बनर्जी ने भाजपा के अनुकूल 'मैदान तैयार करने' की साजिश करार दिया है। तृणमूल का तर्क है कि असम जैसे राज्यों में आयोग का यह कठोर रवैया अदृश्य रहा, जो उसकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। राज्य में आर.एन. रवि जैसे विवादास्पद राज्यपाल की नियुक्ति ने इस अग्नि में घी का कार्य किया है।

ममता बनर्जी की राजनैतिक दीर्घायु का मुख्य आधार उनकी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। 'लक्ष्मी भंडार' जैसी योजनाओं ने ग्रामीण बंगाल की महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तृणमूल के वोट बैंक को एक अभेद्य दुर्ग में परिवर्तित कर दिया है। हालिया अंतरिम बजट में 'युवा साथी योजना' और लक्ष्मी भंडार की राशि में वृद्धि कर ममता ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इसके प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बंगाल यात्राओं के दौरान केंद्र की जन-कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार सृजन और समग्र विकास के भाजपाई दृष्टिकोण को जनता के सम्मुख रखा है। यहां लड़ाई 'राज्य बनाम केंद्र' के लाभों की है।

भाजपा के लिए 'घुसपैठ' सदैव एक उर्वर मुद्दा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पुनः संकल्प दोहराया है कि वे राज्य की डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) में हो रहे अवांछित परिवर्तनों को रोकने के लिए 'अवैध घुसपैठियों' - विशेषकर बांग्लादेश की सीमाओं से आने वाले तत्वों - को निष्कासित करेंगे। प्रधानमंत्री सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के माध्यम से मतुआ समुदाय को नागरिकता देने का आश्वासन दे रहे हैं, किंतु धरातल पर दस्तावेजों की कमी के कारण अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। तृणमूल इसे भाजपा की 'विभाजनकारी नौटंकी' बताकर खारिज कर रही है।

यद्यपि तृणमूल ने संसद में 40 प्रतिशत महिला भागीदारी सुनिश्चित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, किंतु आरजी कर अस्पताल कांड और दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज जैसी घटनाओं ने राज्य में महिला सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। भाजपा ने इस

संवेदनशील मुद्दे को अपने चुनावी अभियान के केंद्र में रखा है और पीड़ित परिवारों को प्रतिनिधित्व देकर जन-संवेदनाओं को झकझोरने का प्रयास किया है। वहीं, तृणमूल अन्य राज्यों की घटनाओं का हवाला देकर भाजपा को 'मूलतः महिला-विरोधी' प्रमाणित करने में जुटी है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बंगाल के रण का अंतिम और सबसे प्रभावी अस्त्र है। तृणमूल निरंतर भाजपा को 'बाहरी' (बहिरागत) पार्टी के रूप में चित्रित करती है, जो बंगाल के प्रतीकों - रवींद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस - को आत्मसात करने का निष्फल प्रयास कर रही है। ममता का तर्क है कि बंगाल का राष्ट्रवाद भाजपा के 'हिंदुत्व' के सांचे में नहीं समा सकता। दूसरी ओर, भाजपा अब बंगाली मनीषियों और स्वतंत्रता सेनानियों के गौरव गान के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास कर रही है कि वह बंगाल की समृद्ध विरासत की वास्तविक संरक्षक है।

यह लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को अपने रंग में रंगने की है। जो भी जीते, उसके परिणाम न केवल हावड़ा ब्रिज के उस पार दिखेंगे, बल्कि दिल्ली के रायसीना हिल्स तक महसूस किए जाएंगे।

असम: ब्रह्मपुत्र की लहरों पर महत्वाकांक्षाओं का ज्वार

9 अप्रैल की ऐतिहासिक तिथि ने केवल मतपेटियों को ही नहीं भरा, बल्कि असम के लाखों नागरिकों की सामूहिक आकांक्षाओं और उनके गुप्त निर्णयों को भी विधिक रूप से सील कर दिया है। मतदान केंद्रों पर उमड़ा जनसैलाब और मतदान प्रतिशत के उच्च आंकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि जनता ने इस लोकतांत्रिक अनुष्ठान में पूर्ण समर्पण के साथ आहुति दी है। किंतु, वास्तविक विद्रूपता आंकड़ों की प्रचुरता में नहीं, बल्कि उस दिशा में निहित है, जिसे पहचानने में राजनैतिक पंडित भी स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। असम का यह चुनाव अब केवल चुनावी गणित का विषय नहीं रहा, बल्कि यह भावनाओं, क्षेत्रीय अस्मिता और दीर्घकालिक सत्ता-संतुलन का एक जटिल समीकरण बन चुका है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस के युवा सारथी गौरव गोगोई के मध्य छिड़ा यह संघर्ष अब अपने उस चरमोत्कर्ष पर है, जहां तर्क मौन हो जाते हैं और केवल परिणाम बोलते हैं। निर्वाचन अभियान के दौरान जो प्रखर और तीक्ष्ण प्रहार देखे गए, उन्होंने इस विमर्श को केवल वैचारिक मतभेदों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक 'व्यक्तिगत साख' के महायुद्ध में परिवर्तित कर दिया।

असम के इतिहास में यह एक दुर्लभ संयोग रहा कि इस बार राजनैतिक भविष्य का निर्धारण 'बिहू' के पवित्र पर्व से पूर्व ही संपन्न हो गया। बिहू केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि असमिया प्राण-तत्व की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। उत्सव के उमंग और चुनावी तनाव का यह मिलन जनता के मनोविज्ञान पर एक गहरा प्रभाव डालता है।

सरमा का आत्मविश्वास उस सांगठनिक सुदृढ़ता पर आधारित है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक दशक में असम के दुर्गम अंचलों और विविध समुदायों के भीतर रोपित किया है। इसके विपरीत, गौरव गोगोई की रणनीति 'परिवर्तन की उस अदृश्य लहर' पर टिकी है, जिसके विषय में उनका दावा है कि वह सत्ता की जड़ों को हिलाने के लिए पर्याप्त है। मतदान के पश्चात यह स्पष्ट है कि यह केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह दो भिन्न राजनैतिक दर्शनों के टकराव का अंतिम प्रतिवेदन है।

धरातल से प्राप्त होने वाले संकेत किसी पहेली की भांति उलझे हुए हैं। महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में भाजपा का अभेद्य कवच सुरक्षित प्रतीत होता है, जहां विकास और सुदृढ़ नेतृत्व के नारों ने मध्यम वर्ग को सम्मोहित किया है। किंतु, ग्रामीण अंचलों से उठने वाले असंतोष के स्वर और आर्थिक मंदी की आहट ने सत्ताधारी दल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विशेष रूप से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जिस प्रकार की राजनैतिक सक्रियता और विपक्षी ध्रुवीकरण देखा गया है, वह किसी बड़े उलटफेर की ओर संकेत कर सकता है। यह अनिश्चितता ही इस चुनाव को एक 'क्लासिक थ्रिलर' (क्लासिक थ्रिलर) का स्वरूप प्रदान कर रही है, जहां कड़े मुकाबले की संभावना ने दोनों पक्षों को सशंकित कर रखा है।

असम के इतिहास में यह एक दुर्लभ संयोग रहा कि इस बार राजनैतिक भविष्य का निर्धारण 'बिहू' के पवित्र पर्व से पूर्व ही संपन्न हो गया। बिहू केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि असमिया प्राण-तत्व की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। उत्सव के उमंग और चुनावी तनाव का यह मिलन जनता के मनोविज्ञान पर एक गहरा प्रभाव डालता है। अब जब मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, असम का जनमानस 'उत्सव के आनंद' और 'परिणाम के संशय' के मध्य एक विचित्र मानसिक अवस्था में खड़ा है।

निर्वाचन की घोषणा से ठीक पूर्व सरमा सरकार ने जिस तीव्रता के साथ 'डैमेज कंट्रोल' (क्षति-निवारण) की गोटियाँ बिछाईं, वह किसी सोची-समझी सामरिक योजना का हिस्सा प्रतीत होती है।

आर्थिक सहायता की वर्षा, युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्रों का समर्पण और 'रुद्र' जैसे कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित डिजिटल अनुप्रयोगों का अनावरण - इन सबके माध्यम से शासन ने अंतिम क्षणों में जनसमर्थन को अपनी ओर मोड़ने का भगीरथ प्रयास किया। अब प्रश्न यह है कि क्या ये 'डिजिटल अस्त्र' और 'तात्कालिक लाभ' मतदाताओं के मन को परिवर्तित करने में सफल रहे, या यह केवल एक भव्य चुनावी प्रबंधन मात्र बनकर रह गया?

कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति के केंद्र में 'असमिया उप-राष्ट्रीयता' को स्थान दिया और क्षेत्रीय दलों के साथ एक साझा मोर्चा निर्मित किया। किंतु, मतदान के पश्चात सबसे प्रखर प्रश्न यही है कि क्या यह गठबंधन धरातल पर एक 'एकीकृत शक्ति' के रूप में क्रियान्वित हुआ, या यह केवल सत्ता की आकांक्षा में किया गया एक 'अवसरवादी समझौता' था? यदि इस एकजुटता के भीतर अविश्वास की दरारें रहीं, तो विपक्ष के लिए परिणाम अत्यंत पीड़ादायक हो सकते हैं।

मतदान के पश्चात का सबसे रोमांचक पक्ष जनता का वह 'मौन' है, जो किसी भी राजनैतिक विश्लेषण को ध्वस्त करने की सामर्थ्य रखता है। अब न रैलियों का कोलाहल है, न भाषणों की गर्जना और न ही आरोपों की वर्षा। किंतु इस निःशब्द वातावरण के भीतर एक सुस्पष्ट निर्णय सुरक्षित है। क्या जनता ने शासन की निरंतरता और स्थिरता को प्राथमिकता दी है? या फिर इस मौन के पीछे 'सत्ता-परिवर्तन' की वह ज्वाला सुलग रही है जो 4 मई को प्रस्फुटित होगी?

दोनों पक्ष अब अपनी 'पोस्ट-रिजल्ट' (पोस्ट-रिजल्ट) रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। भाजपा अपने सांगठनिक तंत्र को सतर्क रखे हुए है, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी प्रत्येक संदेहास्पद संकेत पर दृष्टि बनाए हुए हैं।

असम का यह निर्णय केवल एक राज्य की सत्ता का निर्धारण नहीं करेगा, बल्कि यह समूचे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक 'राजनैतिक प्रकाश-स्तंभ' सिद्ध होगा। यदि भाजपा यहाँ अपनी सत्ता की रक्षा करने में सफल होती है, तो उसका क्षेत्रीय प्रभुत्व एक नए शिखर को स्पर्श करेगा। किंतु, यदि विपक्ष अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करता है, तो यह भारतीय राजनीति में एक नए शक्ति-संतुलन के अभ्युदय का शंखनाद होगा।

मतपेटियां बंद हैं, किंतु राजनीति का वास्तविक द्वार अब खुलने को है। 4 मई 2026 को जब नियति का पिटारा खुलेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि असम ने स्थिरता का वरदान दिया है या परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है।

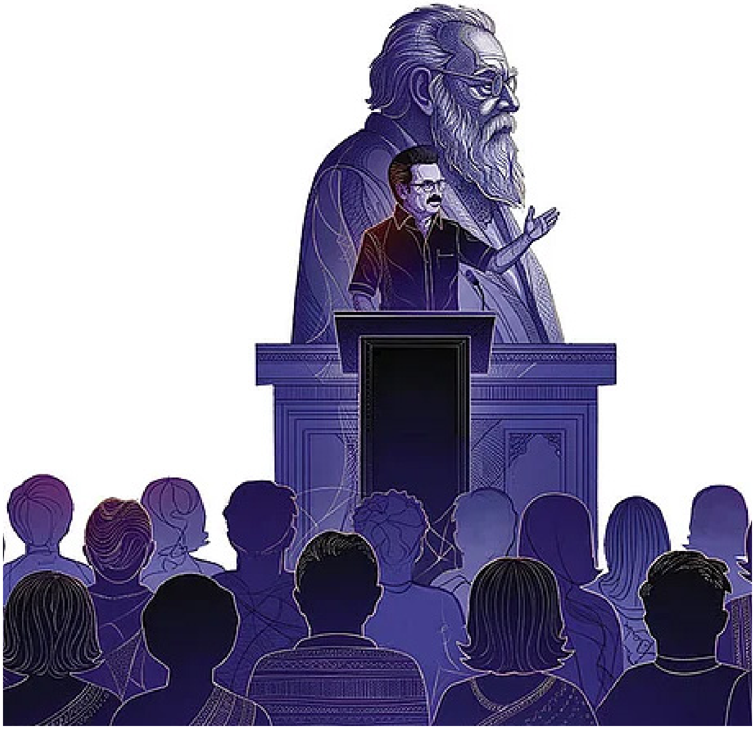

मुख्यमंत्री रंगास्वामी के नेतृत्व वाली एन.आर. कांग्रेस-भाजपा गठबंधन सरकार के लिए यह निर्वाचन केवल सत्ता की रक्षा का उपक्रम नहीं, बल्कि उनके कार्यकाल पर जनता के अंतिम प्रतिवेदन की कसौटी है। 2021 में जिस 'डबल इंजन' (डबल इंजन) के नैरेटिव ने पुदुच्चेरी को विकास और स्थिरता का स्वप्न दिखाया था, आज वही दावा जन-अदालत में कठघरे में खड़ा है।

पुदुच्चेरी: फ्रांसीसी झरोखों से झांकता 'डबल' इम्तहान

पुदुच्चेरी के नीले समंदर की लहरें सामान्यतः शांति का संदेश देती हैं, किंतु 9 अप्रैल की संध्या के पश्चात यहाँ का वातावरण एक रहस्यमयी राजनैतिक मंथन का साक्षी बन चुका है। महज 30 सीटों वाली लघु विधानसभा वाला यह केंद्र शासित प्रदेश आज परिणामों की उस देहरी पर खड़ा है, जहाँ पहचान की राजनीति और व्यवस्था के प्रति उपजा रोष एक नया समीकरण गढ़ रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार, मतदान का प्रतिशत न केवल संतुलित रहा, बल्कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और अर्ध-शहरी अंचलों में मतदाताओं की सक्रियता ने राजनैतिक पंडितों को विस्मय में डाल दिया है। यह प्रतिमान स्पष्ट करता है कि यह चुनाव केवल 'गठबंधन की गणित' नहीं, बल्कि स्थानीय यथार्थ और जन-संवेदनाओं का एक सघन अधि-वृतांत बन चुका है।

मुख्यमंत्री रंगास्वामी के नेतृत्व वाली एन.आर. कांग्रेस-भाजपा गठबंधन सरकार के लिए यह निर्वाचन केवल सत्ता की रक्षा का उपक्रम नहीं, बल्कि उनके कार्यकाल पर जनता के अंतिम प्रतिवेदन की कसौटी है।

2021 में जिस 'डबल इंजन' (डबल इंजन) के नैरेटिव ने पुदुच्चेरी को विकास और स्थिरता का स्वप्न दिखाया था, आज वही दावा जन-अदालत में कठघरे में खड़ा है। यद्यपि सरकार ने केंद्र के साथ समन्वय और विकास योजनाओं को अपनी महती उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु मतदान के पश्चात उभरने वाले संकेत एक भिन्न ही सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में दर्ज किया गया मौन असंतोष यह इंगित करता है कि विकास के दावों और धरातल की विसंगतियों के मध्य एक अगाध खाई विद्यमान है।

इस निर्वाचन का सबसे सूक्ष्म, किंतु सर्वाधिक विनाशकारी मुद्दा रसोई गैस (एलपीजी) का संकट सिद्ध हुआ है। बढ़ती हुई कीमतें, आपूर्ति की अनियमितता और घरेलू बजट पर पड़ता अतिरिक्त दबाव - इन कारकों ने साधारण मतदाता के भीतर एक ऐसी राजनैतिक ऊष्मा उत्पन्न की है, जिसने बड़े-बड़े विमर्शों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। विशेषकर महिलाओं और निम्न-मध्यम वर्ग के बीच यह विषय एक निर्णायक कारक बनकर उभरा है। मतदान के पैटर्न (पैटर्न) से यह आभास होता है कि रसोई की यह आंच सत्ताधारी गठबंधन के 'विकास-वाद' को झुलसाने की सामर्थ्य रखती है।

कांग्रेस-द्रमुक गठबंधन ने इस बार सत्ता पक्ष को एक सुदृढ़ चुनौती देने का भगीरथ प्रयास किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों की सफलता ने विपक्षी खेमे में आत्मविश्वास का संचार तो किया, किंतु सीटों के तालमेल और नेतृत्व के प्रश्नों ने उनके भीतर व्याप्त खटास को भी सार्वजनिक कर दिया। विपक्षी खेमा यद्यपि सत्ता-परिवर्तन के प्रति आशावादी है, किंतु यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि क्या उनका आंतरिक असंतुलन परिणामों के समय 'आत्मघाती' सिद्ध होगा? पुदुच्चेरी की प्रबुद्ध जनता ने विपक्ष के इस अंतर्विरोध को किस दृष्टि से देखा है, इसका प्रकटीकरण 4 मई को ही संभव होगा।

पुदुच्चेरी के इस संकुचित चुनावी रणक्षेत्र में 'तमिलार काछि' जैसे लघु दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रभाव इस बार अप्रत्याशित रहा है। जिन सीटों पर कड़े और त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है, वहां ये सूक्ष्म राजनैतिक इकाइयां 'किंगमेकर' (किंगमेकर)

की भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। यह पुदुच्चेरी की विशिष्ट राजनैतिक संस्कृति का ही परिचायक है कि यहाँ छोटे-छोटे समूह भी बड़े अधिष्ठानों के समीकरणों को ध्वस्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। पुदुच्चेरी का यह निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दक्षिण भारत में उनकी दीर्घकालिक विस्तारवादी रणनीति की एक महत्वपूर्ण 'राजनैतिक प्रयोगशाला' है। यदि यह गठबंधन पुनः सत्ता प्राप्त करने में सफल होता है, तो यह भाजपा के दक्षिणी विस्तार को एक नई ऊर्जा और विधिक मान्यता प्रदान करेगा। इसके विपरीत, यदि परिणाम प्रतिकूल रहे, तो यह उनके 'डबल इंजन' मॉडल पर गंभीर प्रश्नचिन्ह अंकित कर सकता है। पुदुच्चेरी आज एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण में खड़ा है, जहाँ सतह पर समंदर की चिर-परिचित शांति है, किंतु गहराई में जनमत का एक प्रचंड तूफ़ान आकार ले रहा है। मतदान के पश्चात का यह अंतराल केवल प्रतीक्षा की घड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि यह एक नए राजनैतिक पुनर्संतुलन की प्रस्तावना है। क्या रंगास्वामी का अनुभव और 'डबल इंजन' का आकर्षण जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा? या पुदुच्चेरी की जनता एक बार फिर अपनी पुरानी राजनैतिक धाराओं की ओर लौटने का निर्णय सुनाएगी? लहरें मौन हैं, किंतु पुदुच्चेरी की राजनीति में नियति का निर्णय अपना शंखनाद करने को आतुर है।

तमिलनाडु: द्रविड़ अस्मिता और राजनैतिक अस्तित्व का महासंग्राम

दक्षिण भारत की राजनीति का हृदय कहा जाने वाला तमिलनाडु आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां प्राचीन द्रविड़ गौरव और आधुनिक राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं का घर्षण एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। कुल 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को होने वाला मतदान केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारात्मक वर्चस्व की लड़ाई है जिसने दशकों से इस राज्य की नियति को गढ़ा है। निर्वाचन की घोषणा से पूर्व ही यहाँ मोर्चेबंदी इस कदर सघन हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के 'द्रविड़ नैरेटिव' ने वातावरण को पूर्णतः चुनावी रंग में रंग दिया। मुख्यमंत्री स्टालिन इस चुनाव को 'एनडीए बनाम तमिलनाडु' के युद्ध के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट है - मुख्य प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) से उसकी द्रविड़ पहचान छीनकर उसे एक ऐसे गठबंधन के हिस्से के रूप में चित्रित करना, जो कथित रूप से तमिल संस्कृति और संघीय ढांचे के विरुद्ध खड़ा है। राज्यपाल आर.एन. रवि के साथ उनका दीर्घकालिक टकराव और विधानसभा के विधेयकों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गई

लड़ाई ने स्टालिन को 'तमिल अधिकारों के रक्षक' के रूप में स्थापित करने में सहायता की है।

इस बार तमिलनाडु के रणांगण में सबसे चर्चित और अनिश्चित तत्व अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (टीवीके) का प्रवेश है। यद्यपि राजनैतिक विश्लेषक उनके वास्तविक चुनावी प्रभाव को लेकर संशय में हैं, किंतु उनकी रैलियों में उमड़ता जनसैलाब पारंपरिक दलों की धड़कनें बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। चर्चाएं तो यहां तक थीं कि भाजपा ने विजय को उप-मुख्यमंत्री पद का प्रलोभन देकर एनडीए में लाने का प्रयास किया, किंतु अपनी स्वतंत्र तमिल पहचान खोने के भय से विजय ने 'एकला चलो' की नीति अपनाई। क्या यह भीड़ वोटों में परिवर्तित होगी या यह केवल एक फिल्मी सितारे के प्रति आकर्षण मात्र है, इसका उत्तर 4 मई के गर्भ में छिपा है।

अन्नाद्रमुक आज अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। जयललिता के अवसान के पश्चात प्रारंभ हुई सत्ता की होड़ ने पार्टी को खंडित कर दिया है। एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) के समक्ष चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि यह सिद्ध करने की भी है कि वरिष्ठ नेताओं के पलायन के उपरांत भी अन्नाद्रमुक ही द्रमुक-विरोधी राजनीति का मुख्य केंद्र है। ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) का द्रमुक की ओर झुकाव दक्षिण तमिलनाडु के 'मुक्कुलतोर' समुदाय के समीकरणों को बिगाड़ सकता है।

तंत्र तथा संघ परिवार के बीच कथित साठगांठ जैसे मुद्दों ने सरकार की छवि को क्षति पहुँचाई है। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर के कारण युवाओं का विदेशों की ओर पलायन एक ऐसा घाव है, जिस पर विपक्ष निरंतर प्रहार कर रहा है।

कांग्रेस के लिए केरलम इस समय देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक आधार है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वायनाड से संलग्नता यह दर्शाती है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व केरलम को अपनी अंतिम शक्ति के रूप में देख रहा है। एक दशक से सत्ता से बाहर रहने के कारण कांग्रेस संगठन में शिथिलता आई है और गुटबाजी चरम पर है। यदि इस बार भी यूडीएफ विफल रहता है, तो उसके सहयोगी दलों, विशेषकर 'इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग', का मोहभंग हो सकता है, जो कांग्रेस के लिए एक अस्तित्वगत संकट (एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस) उत्पन्न कर देगा।

राज्य में भाजपा का वोट शेयर निरंतर बढ़ रहा है, जो कांग्रेस और वामपंथियों के लिए चिंता का विषय है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी, जिससे एनडीए को इस बार कम से कम 3 से 5 सीटें जीतने की आशा है। केरलम की राजनीति में 48 प्रतिशत अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम मतदाताओं का यूडीएफ की ओर झुकाव और ईसाई मतदाताओं के एक वर्ग का भाजपा की ओर बढ़ता रुझान इस बार के नतीजों को अप्रत्याशित बना सकता है।

वहीं, भाजपा यहाँ 'लॉन्ग टर्म' (दीर्घकालिक) खेल खेल रही है। के. अन्नामलाई के सांगठनिक प्रयोगों और वर्तमान नेतृत्व के बीच के अंतर्विरोधों के मध्य भाजपा की दृष्टि 2031 के चुनावों पर है। पार्टी का लक्ष्य अन्नाद्रमुक को हाशिये पर धकेलकर तमिलनाडु के मुकाबले को 'द्रमुक बनाम भाजपा' में परिवर्तित करने का है।

केरलम: विचारधारा की अंतिम शरणस्थली और अस्तित्व का संकट

केरलम, जिसे 'ईश्वर का अपना देश' कहा जाता है, आज अपनी 16वीं विधानसभा के निर्वाचन के लिए सन्नद्ध है। यहां की राजनीति दशकों से दो ध्रुवों - एलडीएफ (वाम मोर्चा) और यूडीएफ (कांग्रेस नीत गठबंधन) - के बीच झूलती रही है। किंतु पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने दोबारा सत्ता में आकर इस चक्र को तोड़ दिया। इस बार का चुनाव न केवल राज्य के लिए, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी राजनीति की प्रासंगिकता के लिए भी निर्णायक है।

पिनराई सरकार ने अपने कार्यकाल में वामपंथ की पारंपरिक जड़ता को त्यागकर विकास और पूंजी निवेश के प्रति एक व्यवहारिक (प्रैग्मेटिक) दृष्टिकोण अपनाया है। बुनियादी ढांचे का विकास और कोविड-19 तथा विनाशकारी बाढ़ के दौरान सरकारी प्रबंधन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। किंतु, आरोपों के काले बादल भी कम सघन नहीं हैं। सबरीमला में स्वर्ण चोरी, भाई-भतीजावाद और पुलिस

नियति का निर्णय व नए भारत की पदचाप

पश्चिम बंगाल के गंगा तटों से लेकर तमिलनाडु के हिंद महासागर तक फैले इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। ये चुनाव केवल राज्यों के मुख्यमंत्री तय नहीं करेंगे, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक वैचारिक 'ब्लूप्रिंट' भी तैयार करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का संघर्ष जहाँ क्षेत्रीय अस्मिता की रक्षा का प्रतीक है, वहीं भाजपा के लिए यह 'अजेय भारत' के स्वप्न की पूर्ति है। असम में हिमंत बिस्वा सरमा की रणनीतिक बिसात पूर्वोत्तर में भगवा ध्वज को स्थायी बनाने की चेष्टा है, तो गौरव गोगोई के लिए यह पिता की विरासत को बचाने का भगीरथ प्रयास है। तमिलनाडु और केरलम में द्रविड़ गौरव और वामपंथी सिद्धांतों की लड़ाई यह तय करेगी कि क्या दक्षिण भारत अभी भी दिल्ली के वैचारिक संवेगों से अछूता रह सकता है। 4 मई 2026 को जब इन चुनावों के परिणाम निकलेंगे, तो राख के नीचे से जो नई राजनैतिक व्यवस्था उभरेगी, वह भारत के संघीय ढांचे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और लोक-कल्याणकारी नीतियों की नई परिभाषा होगी। यह युद्धों का अंत नहीं, बल्कि एक नए भारत की शुरुआत है, जहाँ जनता का निर्णय ही अंतिम महामंत्र है। ●

लाल अंत

संतोष कुमार

बंदूकों के बाद का सवाल

छत्तीसगढ़ के कुतुल में 'ढला लाल साया' अब सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नए द्वंद्व की शुरुआत है। माओवादी खौफ के बाद यहां विकास की दस्तक तो है, लेकिन उसके साथ न्याय, विस्थापन और भरोसे के कठिन सवाल भी खड़े हैं।

छत्तीसगढ़ के उन घने, आदिम और रहस्यमयी जंगलों के बीच बसा कुतुल गांव, जो कभी माओवादी विद्रोह की 'अघोषित राजधानी' था, आज एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। यहाँ की हवाओं में अब बारूद की उस तीखी गंध के बजाय, आधुनिकता की एक धीमी लेकिन मद्धम दस्तक सुनाई दे रही है। दशकों तक जहाँ बंदूकों की गूंज और दबे पांवों की आहट ही एकमात्र कानून थी, वहाँ अब 'विकास' की एक नई और शायद थोड़ी डरावनी लहर पहुंच रही है। 2026 की पहली तिमाही तक भारत सरकार का यह दावा एक कठोर वास्तविकता में बदल चुका है - दुनिया का सबसे लंबा और खूनी माओवादी विद्रोह अपने अंतिम सूर्यास्त के करीब है। कुतुल की गलियों से लाल झंडे उतर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ 'न्याय का सूरज' उगेगा, यह आज भी एक यक्ष प्रश्न है।

खौफ का वह काला अध्याय

कुतुल के आदिवासियों के लिए माओवादी 'जंगल राज' कोई क्रांतिकारी स्वप्न नहीं, बल्कि एक दमनकारी कारावास था। उन्होंने आदिवासियों को बड़े प्रोजेक्ट्स और बांधों से बचाने के नाम पर

अपने जाल में फंसाया, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने इस समुदाय को केवल अपना 'मोहरा' बनाया। स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर बताते हैं कि कैसे विद्रोहियों ने शिक्षा का गला घोंट दिया था; वे नहीं चाहते थे कि बच्चा पांचवीं कक्षा से आगे पढ़े, क्योंकि पढ़ा-लिखा आदिवासी सवाल पूछता है, और माओवाद केवल 'आदेश' पर पलता है।

इन 'सिद्धांतों' के ठेकेदारों की कंगारू अदालतों ने मौत के फरमान सुनाने में कभी देर नहीं की। वे समानता की बात करते थे, लेकिन उनके शीर्ष कमांडर बाहरी और ऊंची जाति के वे लोग थे, जो स्थानीय आदिवासियों को तुच्छ काम करने और बोरियत भरे कम्युनिस्ट लेक्चर सुनने पर मजबूर करते थे। यह विचारधारा नहीं, बल्कि खौफ का एक ऐसा तंत्र था, जिसने पूरे क्षेत्र की आत्मा को ही कुचल दिया था।

आत्मसमर्पण और 'पुचकार और फटकार' का खेल

राज्य ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए 'पुचकार और फटकार' की नीति को एक कला की तरह अपनाया है। एक तरफ सुरक्षा बलों ने 2024 से अब तक उन 748 लड़ाकों को मिटा दिया है, जो कभी इस जंगल के 'अजेय' सितारे माने जाते थे, तो दूसरी तरफ आत्मसमर्पण करने वालों के लिए सरकारी तिजोरियां खोल दी गई हैं। आज 'कॉमरेड अरब' जैसे खूंखार कमांडर, जिनके हाथ सैकड़ों हत्याओं के रक्त से सने थे, अब पुनर्वास केंद्रों में फूलों वाली कमीज पहनकर माफी मांग रहे हैं।

यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक विजय है। जब पूर्व माओवादी अब 'डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड' की वर्दी पहनकर अपने ही पुराने साथियों का शिकार करते हैं, तो माओवाद की 'वैचारिक रीढ़' टूट जाती है। यह एक ऐसा शतरंज का खेल है, जहाँ सरकार ने विद्रोही के अपने ही प्यादों को उसी के खिलाफ वजीर बना दिया है।

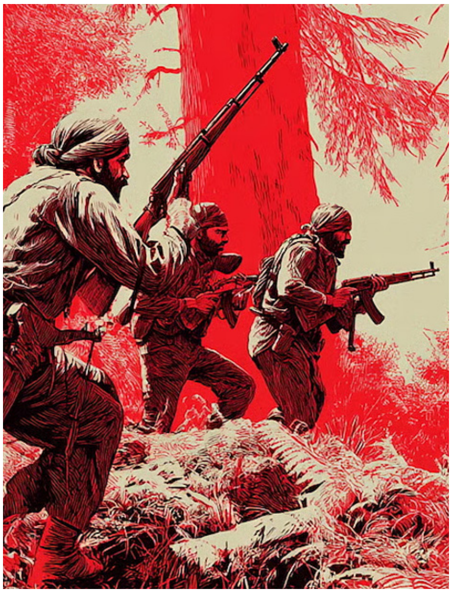

कुतुल के जंगलों से लाल साया भले ढल रहा हो, लेकिन सच्ची कहानी अब शुरू होती है – जहां बंदूकों की जगह बुलडोज़र ले सकते हैं और खौफ की जगह अनिश्चितता। सवाल वही है– क्या विकास आदिवासियों का होगा, या उनके ऊपर थोप दिया जाएगा?

विकास बनाम विस्थापन

जैसे ही जंगलों से माओवादियों के पैर उखड़े, विकास की एक तेज और आक्रामक लहर वहां पहुंची है। कुतुल में इंटरनेट, पक्की सड़कें और आधार कार्ड का पहुँचना डिजिटल इंडिया का सपना तो है, लेकिन इस चमक के नीचे एक गहरा भय भी दबा है। आदिवासियों के भीतर यह शंका घर कर गई है कि विद्रोहियों को खदेड़ने का असली एजेंडा क्या है? क्या यह उनकी ज़मीन को 'कॉर्पोरेट खदानों' के लिए साफ करने की एक सोची-समझी साजिश है?

उन्हें डर है कि माओवादियों का 'जंगल राज' खत्म होने के बाद अब उन पर 'खनन राज' थोपा जाएगा। जंगल, जो उनका भगवान था और उनकी पहचान था, अब लोहे के अयस्क और बेशकीमती खनिजों के एक 'कच्चे माल' की तरह देखा जा रहा है। कुतुल की कहानी आज भारत के उस चौराहे की कहानी है, जहाँ एक तरफ डिजिटल इंडिया का भव्य सपना है और दूसरी तरफ अपनी जड़ों को बचाने की एक आखिरी जद्दोजहद। यदि जंगल से माओवाद खत्म होने के बाद वहां केवल जेसीबी मशीनें ही दिखेंगी, तो 'कॉमरेड अरब' जैसे लोग फिर से पैदा होने में देर नहीं लगाएंगे।

क्या यह वाकई अंत है?

गृह मंत्रालय का 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य एक रणनीतिक और राजनीतिक बयानबाजी का मिश्रण है। 800 जिलों में से केवल सात में ही अब माओवाद की अंतिम सांसे चल रही हैं। लेकिन शांति का अर्थ केवल बंदूकों का शांत होना नहीं है। असली चुनौती यह है कि भारत उस आदिवासी विश्वास को कैसे बहाल करे, जो दशकों से राज्य और विद्रोहियों की इस 'क्रॉसफायर' में पिस रहा है। बंदूकें तो शांत हो जाएंगी, लेकिन अगर न्याय और सम्मान की स्थापना नहीं हुई, तो यह शांति एक 'अस्थायी युद्धविराम' से अधिक कुछ नहीं होगी।

कुतुल आज भारत के उस चौराहे पर खड़ा है, जहाँ उसे यह तय करना है कि वह अपनी जड़ों का सम्मान करता है या केवल खनिजों की खुदाई में अपनी समृद्धि देखता है। जंगल राज खत्म हो रहा है, लेकिन न्याय का राज स्थापित होना अभी बाकी है। बस्तर की फिजा बदल रही है, लेकिन उसका हृदय आज भी धड़कते हुए सवालों से भरा है। विकास आना चाहिए, लेकिन वह विकास आदिवासियों की शर्तों पर होना चाहिए, न कि कॉर्पोरेट घरानों की मशीनरी के नीचे। यह बस्तर के पुनर्निर्माण की अंतिम और सबसे कठिन लड़ाई है। ●

रॉकेट फोर्स युद्ध का नया व्याकरण

आधुनिक युद्ध अब सीमाओं की टकराहट नहीं, बल्कि तकनीक, गति और सटीकता के उस अदृश्य संग्राम में बदल चुका है, जहाँ निर्णय पलों में होते हैं। ऐसे समय में रॉकेट और मिसाइल का एकीकरण भारत की रणनीतिक अनिवार्यता बन चुका है।

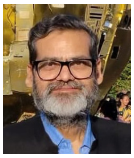

संजय श्रीवास्तव

कभी युद्ध रणभूमि पर आमने-सामने खड़ी सेनाओं का टकराव होता था - धूल, धुआँ और ध्वनि का एक जीवंत दृश्य। लेकिन इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में युद्ध का यह दृश्य लगभग विलुप्त हो चुका है। अब युद्ध किसी सीमा रेखा पर नहीं, बल्कि उपग्रहों, सेंसरों, एल्गोरिद्म और कृत्रिम मेधा के अदृश्य जाल में लड़ा जा रहा है।

यह वह युग है जहाँ 'किल चेन' - यानी लक्ष्य की पहचान से लेकर उसके विनाश तक की पूरी प्रक्रिया - सेकंडों में पूरी हो जाती है। निर्णय लेने की गति ही अब जीत और हार के बीच की रेखा बन गई है। इस नए युद्धशास्त्र में जो पहले देखेगा, पहले समझेगा और पहले प्रहार करेगा - वही विजेता होगा।

ऐसे परिवेश में रॉकेट और मिसाइल अब केवल हथियार नहीं, बल्कि उस रणनीतिक तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग बन चुके हैं, जो युद्ध के पूरे शरीर को संचालित करता है।

एकीकरण की आवश्यकता: विखंडन से समेकन तक

भारत की सैन्य संरचना में अब तक रॉकेट और मिसाइल क्षमताएँ विभिन्न इकाइयों में विभाजित रही हैं - कोर ऑफ आर्टिलरी, सामरिक बल कमांड और अन्य विशेष इकाइयाँ। यह व्यवस्था उस समय तक पर्याप्त थी, जब युद्ध अपेक्षाकृत धीमी गति और स्पष्ट सीमाओं के भीतर लड़ा जाता था।

लेकिन आज की युद्धभूमि 'रियल टाइम' है। यहाँ विखंडन का अर्थ है - विलंब, और विलंब का अर्थ है - पराजय। इसी कारण 'इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स' की अवधारणा केवल एक संगठनात्मक सुधार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक क्रांति है।

यह एकीकरण भारत की बिखरी हुई मारक क्षमताओं को एकीकृत कर उन्हें 'सिनर्जी' में बदल देगा - जहाँ रॉकेट की तीव्रता, मिसाइल की सटीकता और ड्रोन की लचीलापन मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करेंगे, जो दुश्मन को प्रतिक्रिया का अवसर ही नहीं देगी।

चीन की बढ़त: ड्रैगन की 'फायरपावर'

यदि आधुनिक युद्ध के इस नए व्याकरण को किसी देश ने सबसे पहले समझा, तो वह चीन है। 2015 में स्थापित 'पीएलए रॉकेट फोर्स' केवल एक सैन्य इकाई नहीं, बल्कि चीन की रणनीतिक

सोच का प्रतीक है।

चीन ने न केवल अपनी मिसाइल क्षमताओं को एकीकृत किया, बल्कि उन्हें सैन्य एआई और 'किल चेन' के साथ जोड़कर एक ऐसा तंत्र विकसित किया, जो लगभग स्वचालित युद्ध संचालन में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल (A2/AD) रणनीतियों तक, चीन ने युद्ध के हर आयाम में बढ़त हासिल करने का प्रयास किया है।

उसका रक्षा बजट, जो इस क्षेत्र में अमेरिका से भी कई गुना अधिक है, इस बात का संकेत है कि वह भविष्य के युद्ध को केवल लड़ना नहीं, बल्कि नियंत्रित करना चाहता है।

पाकिस्तान का समीकरण: द्विमुखी चुनौती

भारत के लिए चुनौती केवल चीन तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी 'आर्मी रॉकेट फोर्स' को तेजी से विकसित किया है। फतेह श्रृंखला की मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम अब भारत के लिए एक वास्तविक खतरा बन चुके हैं।

यदि चीन और पाकिस्तान की क्षमताएँ एक साथ सक्रिय होती हैं, तो यह भारत के लिए एक 'द्विमुखी दबाव' की स्थिति उत्पन्न कर सकती है - उत्तर और पश्चिम, दोनों दिशाओं से।

यही वह परिदृश्य है, जिसने भारत को अपनी रक्षा रणनीति को पुनःपरिभाषित करने के लिए बाध्य किया है।

भविष्य का युद्ध: 'स्मार्ट' विनाश का युग

आधुनिक मिसाइलें अब 'ब्लंट फोर्स' नहीं रहीं। वे अब 'सर्जिकल प्रहार' की क्षमता से लैस हैं। जहाँ पहले एक शहर को नष्ट करने के लिए बमबारी की जाती थी, वहीं अब एक विशेष लक्ष्य - एक रनवे, एक कमांड सेंटर या एक मोबाइल लॉन्चर - को सटीकता से ध्वस्त किया जा सकता है।

इससे भी आगे, 'स्वार्म वॉरफेयर' का युग तेजी से आकार ले रहा है। दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें एक साथ, एक नेटवर्क के रूप में, लक्ष्य पर आक्रमण करेंगी। वे आपस में संवाद करेंगी, निर्णय लेंगी और आवश्यकता पड़ने पर अपने लक्ष्य बदलेंगी।

यह युद्ध अब केवल शक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का खेल बन चुका है।

भारत की रणनीतिक छलांग: 'प्रतिक्रिया' से 'प्रहार' तक

इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकती है। यह उसे केवल प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति से एक 'प्रारंभिक प्रहार' करने वाली शक्ति में बदल सकती है।

कमांड चेन के संक्षिप्त होने से निर्णय लेने की गति बढ़ेगी। विभिन्न हथियार प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय होगा। और सबसे महत्वपूर्ण - भारत अपनी सीमाओं के भीतर से ही दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को सटीकता से निशाना बना सकेगा।

यह क्षमता भारत को अपने परमाणु हथियारों को 'डिटरेंस' के रूप में सुरक्षित रखते हुए पारंपरिक संघर्षों में बढ़त दिला सकती है।

एआई और 'किल चेन': युद्ध का मस्तिष्क

भविष्य का युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि डेटा और एल्गोरिद्म का होगा। एआई समर्थित 'किल चेन' - जहाँ लक्ष्य की पहचान, विश्लेषण और विनाश एक ही तंत्र के भीतर होते हैं - इस युद्ध का मस्तिष्क होगी। भारत यदि इस क्षेत्र में पीछे रह जाता है, तो उसकी मारक क्षमता भी सीमित हो जाएगी। इसलिए इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को केवल हार्डवेयर के रूप में नहीं, बल्कि एक 'स्मार्ट सिस्टम' के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

रणनीतिक संतुलन और वैश्विक संदेश

भारत का यह कदम केवल सैन्य सुधार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट वैश्विक संदेश भी है - कि वह अब केवल एक रक्षात्मक शक्ति नहीं, बल्कि एक सक्रिय रणनीतिक खिलाड़ी है।

यह दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को पुनःपरिभाषित कर सकता है और भारत को 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका में स्थापित कर सकता है।

युद्ध का नया धर्म

युद्ध का स्वरूप बदल चुका है, और इसके साथ ही उसकी नैतिकता और रणनीति भी। अब यह केवल साहस का नहीं, बल्कि गति, सटीकता और बुद्धिमत्ता का खेल है। रॉकेट और मिसाइल का यह एकीकरण भारत के लिए केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनिवार्यता है। यदि भारत इस परिवर्तन को समय रहते पूरी तरह आत्मसात कर लेता है, तो वह न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर पाएगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी अपनी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कर सकेगा।

क्योंकि आधुनिक युद्ध में एक ही नियम है - जो समय से पहले तैयार है, वही विजेता है। ●

किल चेन

भविष्य के युद्ध का अदृश्य तंत्र

आधुनिक युद्ध का स्वरूप अब मूलतः बदल चुका है। शक्ति का केंद्र केवल हथियारों के भंडार में नहीं, बल्कि उस 'किल चेन' में निहित है, जो लक्ष्य की पहचान से लेकर उसके विनाश तक की संपूर्ण प्रक्रिया को एकीकृत करती है। यह एक ऐसा बहुस्तरीय तंत्र है, जिसमें अंतरिक्ष, वायु, समुद्र और भूमि – सभी आयाम एक साथ जुड़कर कार्य करते हैं।

इस प्रणाली की पहली कड़ी होती है – निगरानी और पहचान। उपग्रह, ड्रोन, रडार और ग्राउंड सेंसर दुश्मन की गतिविधियों का सूक्ष्म डेटा एकत्र करते हैं। दूसरी कड़ी में कृत्रिम मेधा और उन्नत विश्लेषण प्रणाली इन आंकड़ों को तत्काल संसाधित कर लक्ष्य की प्राथमिकता और खतरे का स्तर निर्धारित करती है। तीसरी और अंतिम कड़ी है – प्रहार, जहाँ रॉकेट, मिसाइल, या स्वायत्त ड्रोन सटीकता के साथ लक्ष्य को नष्ट करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गति और समन्वय है। 'देखो–समझो–मारो' की पारंपरिक अवधारणा अब 'तुरंत पहचानो और तत्काल प्रहार करो' में बदल चुकी है। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध 'नेटवर्क–सेंट्रिक' और 'डाटा–संचालित' हो गया है, जहाँ सूचना ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है।

आज 'स्वार्म टेक्नोलॉजी' इस किल चेन को और अधिक घातक बना रही है। दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें आपस में संवाद करते हुए लक्ष्य पर समन्वित हमला कर सकती हैं। यदि एक इकाई नष्ट होती है, तो दूसरी स्वतः उसका स्थान ले लेती है – युद्ध अब मशीनों के बीच भी लड़ा जा रहा है।

चीन और अमेरिका इस क्षेत्र में पहले ही बड़ी बढ़त बना चुके हैं, जबकि भारत भी अपने एकीकृत रॉकेट–मिसाइल ढांचे के माध्यम से इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। आने वाले समय में युद्ध वही जीतेगा, जिसकी 'किल चेन' सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे बुद्धिमान होगी – क्योंकि अब युद्धक्षेत्र सीमाओं में नहीं, बल्कि डेटा और निर्णय की गति में तय होगा। ●

डिजिटल विद्रूपता का नया युग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में सत्य और मिथ्या की विभाजक रेखा लुप्त हो चुकी है। दुष्प्रचार के इस महाविस्फोट ने भारत को एक ऐसे डिजिटल रणक्षेत्र में धकेल दिया है, जहां हर ध्वनि और दृश्य अब संदेह के गहरे घेरे में है।

जलज श्रीवास्तव

जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ने दुष्प्रचार की विभीषिका को पंख दे दिए हैं। वह समय अब इतिहास की धुंध में विलीन हो चुका है जब मिथ्या विमर्श गढ़ने के लिए अपार श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती थी। आज एआई ने दुष्प्रचार की निर्माण लागत को न्यूनतम कर उसका 'लोकतांत्रिकरण' कर दिया है। यह आलेख उस अंधकारमय परिदृश्य की पड़ताल करता है जहां एआई-संचालित भ्रांतियां हमारे वर्तमान विधिक ढांचे को चुनौती दे रही हैं और एक ऐसे 'एआई शासन मॉडल' (एआई गवर्नेंस मॉडल) की मांग कर रही हैं जो सुरक्षा और अटूट विश्वास की नींव पर खड़ा हो।

'न्यूजगार्ड' की नवीनतम रिपोर्ट एक भयावह सत्य का उद्घाटन

करती है। एआई द्वारा संचालित 'न्यूज साइट्स' की संख्या अब 16 भाषाओं में 2,089 को लांघ चुकी है। इन डिजिटल केंद्रों पर मानवीय विवेक की उपस्थिति शून्य है। अगस्त 2025 तक प्रमुख 'चैटबॉट्स' द्वारा मिथ्या सूचनाएं परोसने की दर 35 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो पूर्व वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है।

आंकड़ों का मायाजाल और संशय का वातावरण

परिवर्तन की यह गति अकल्पनीय है। वर्ष 2024 में डिजिटल पटल पर हर पांच मिनट में एक 'डीपफेक' प्रहार अंकित किया गया। जालसाजी की यह तीव्रता केवल आर्थिक क्षति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे 'प्रत्यक्ष प्रमाण' की अवधारणा पर ही प्रश्नचिन्ह लगाती है। वर्तमान विद्रूपता यह है कि किसी घोटाले में आकंठ डूबा राजनेता भी अब स्वयं को बेकसूर सिद्ध करने के लिए किसी भी वास्तविक वीडियो को 'डीपफेक' बताकर सत्य का गला घोंट सकता है।

सितंबर 2025 में बीजिंग स्थित 'गोलेक्सी' कंपनी के लीक हुए दस्तावेजों ने 'स्मार्ट प्रोपेगेंडा सिस्टम' के अस्तित्व को उजागर किया। यह कृत्रिम मानवों की एक ऐसी वाहिनी है जो वास्तविक मनुष्यों की भांति चिंतन करने और समाज को प्रभावित करने में सक्षम है। यह प्रणाली 'एलएलएम ग्रूमिंग' जैसी तकनीक के माध्यम से पक्षपातपूर्ण डेटा का जाल बिछाकर वैश्विक जनमत को दूषित कर रही है।

भारतीय संदर्भ: 47 प्रतिशत का अभिशप्त आंकड़ा

भारत आज एआई जनित दुष्प्रचार का सबसे उर्वर केंद्र बन चुका है। सांख्यिकी के अनुसार, 47 प्रतिशत भारतीय वयस्क एआई 'वॉयस-क्लोनिंग' या डीपफेक घोटालों के पाश में बंध चुके हैं, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। यह संकट दो स्तरों पर राष्ट्र को पंगु बना रहा है। प्रथम, राष्ट्रीय सुरक्षा - जहां संकट काल में जमीनी यथार्थ को विद्रूप करने के लिए कृत्रिम सामग्री का उपयोग हो रहा है।

पहलगाम: सूचना युद्ध का रक्तरंजित अध्याय

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के उपरांत जो घटित हुआ, वह आधुनिक सूचना युद्ध का एक क्लासिक उदाहरण है। जब समूचा राष्ट्र 26 बलिदानियों के शोक में डूबा था, तब 'टेलीग्राम' और 'एक्स' जैसे प्लेटफॉर्म एआई-रचित भ्रामक बयानों के श्मशान में तब्दील हो गए। डीपफेक वीडियो के माध्यम से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की छवि का दुरुपयोग किया गया ताकि सांप्रदायिक विद्वेष की अग्नि को प्रज्वलित किया जा सके। यद्यपि प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने सात प्रमुख भ्रांतियों की पहचान की, किंतु तब तक जन-विश्वास की अपूरणीय क्षति हो चुकी थी।

अश्लीलता का डिजिटल अस्त्र और विधिक संकट

जनवरी 2026 में 'ग्रोक एआई' के माध्यम से एक महिला की प्रोफाइल छवि को अश्लील डीपफेक में बदलने का प्रकरण सामने आया। 'एक्स' प्लेटफॉर्म की निष्क्रियता और अपराधी के निर्भीक दुस्साहस ने डिजिटल सुरक्षा के दावों की कलई खोल दी। इसके पश्चात, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि यदि प्लेटफॉर्म 'उचित सावधानी' का पालन नहीं करते, तो उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत प्राप्त 'सुरक्षित आश्रय' की विधिक छूट से वंचित कर दिया जाएगा।

समाधान की दिशा: विधिक और तकनीकी सुरक्षा कवच

एआई के इस भस्मासुर को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतिक कदम अनिवार्य हैं:

1. **जोखिम वर्गीकरण का स्तरीय ढांचा:** राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली एआई सामग्री को अनिवार्य अनुपालन के दायरे में लाया जाना चाहिए।

2. **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही:** जब कोई प्लेटफॉर्म अपने इंटरफेस में एआई टूल्स (जैसे ग्रोक) को एकीकृत करता है, तो वह केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि निर्माता बन जाता है। ऐसी स्थिति में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत उसकी जवाबदेही पूर्ण होनी चाहिए।

3. **अनिवार्य वॉटरमार्किंग और मेटाडाटा:** फरवरी 2026 के संशोधनों के अनुसार, एआई सामग्री के लिए 'मेटाडाटा ट्रेसिंग' अनिवार्य है। वॉटरमार्किंग तकनीक इसे और अधिक प्रखर बनाएगी जिससे दुष्प्रचार के उद्गम तक पहुंचना सरल होगा।

4. **संकटकालीन प्रोटोकॉल:** धारा 69-ए के तहत सामग्री को ब्लॉक करने की प्रक्रिया में गति लाना अनिवार्य है। भारत के एआई शासन दिशानिर्देशों द्वारा प्रस्तावित 'एआई सुरक्षा संस्थान' को एआई सामग्री की शिनाख्त के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी बनाया जाना चाहिए।

भविष्य की चुनौती

एआई दुष्प्रचार केवल तकनीकी समस्या नहीं है, यह हमारे विवेक और लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम तकनीक को कैसे रोकते हैं, बल्कि यह है कि हम सत्य की पहचान करने वाले संस्थानों को कैसे सुदृढ़ करते हैं। यदि हम आज सचेत नहीं हुए, तो डिजिटल संसार का यह कुहासा हमारे वास्तविक अस्तित्व को भी लील जाएगा। ●

थोरियम का शंखनाद

अनवर हुसैन

कलपक्कम की धरा से उठा परमाणु ऊर्जा का नया स्वर भारत को ऊर्जा संप्रभुता के शिखर की ओर ले जा रहा है। स्वदेशी 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' की सफलता मात्र एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत के 'अजेय' होने का उद्‌घोष है।

6 अप्रैल की वह रात्रि, जब घड़ी की सुइयां 9.41 का अंक स्पर्श कर रही थीं, भारत के डिजिटल पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश प्रतिध्वनित हुआ। वह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि भारत के असैन्य परमाणु सफर की उस महती सफलता का आधिकारिक प्रतिवेदन था, जिसने विश्व के परमाणु मानचित्र को सदैव के लिए परिवर्तित कर दिया। 'भारत के लिए गर्व का पल' - इन शब्दों के पीछे छिपी थी कलपक्कम के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दशकों की साधना। तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित स्वदेशी 'प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' ने 'क्रिटिकैलिटी' हासिल कर ली थी। यह उस धुरंधर शक्ति का अभ्युदय था, जिसका स्वप्न स्वतंत्र भारत के प्रथम नेतृत्व ने सात दशक पूर्व देखा था।

भाभा का विजन: पराधीनता से आत्मनिर्भरता तक

भारत के परमाणु कार्यक्रम की जड़ें 1954 के उस कालखंड में निहित हैं, जब परमाणु विज्ञान के पुरोधा होमी जहांगीर भाभा ने तीन चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा गढ़ी थी। भारत की भौगोलिक विवशता यह थी कि यहाँ यूरेनियम का भंडार वैश्विक संपदा का मात्र 2 प्रतिशत था, किंतु थोरियम के मामले में विधाता ने भारत पर विशेष अनुकंपा की थी - विश्व का 25 प्रतिशत थोरियम भंडार भारत की कोख में सुरक्षित है। भाभा का तर्क स्पष्ट था: यदि भारत को अपनी बढ़ती जनसंख्या और प्रगाढ़ होती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा संप्रभुता प्राप्त करनी है, तो उसे यूरेनियम की पराधीनता त्यागकर थोरियम की अनंत ऊर्जा को अपनाना होगा। कलपक्कम की यह सफलता उसी 'द्वितीय सोपान' (स्टेज 2) का साकार रूप है, जो भारत को थोरियम आधारित भविष्य (स्टेज 3) की ओर अग्रसर करती है।

थोरियम का रहस्यमयी रूपांतरण

भारत के पास लगभग 4 लाख टन थोरियम का विशाल भंडार है। तकनीकी दृष्टि से थोरियम स्वयं 'विखंडनीय' (Fissile) नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन के टकराने से यह सीधे ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता। किंतु, विज्ञान की जादुई प्रक्रिया के अंतर्गत जब इसे रिएक्टर में रखा जाता है, तो यह 'यूरेनियम-233' में रूपांतरित हो जाता है। यही यूरेनियम-233 वह ईंधन है, जो भारत की शताब्दियों की ऊर्जा पिपासा को शांत करने की सामर्थ्य रखता है।

परमाणु ऊर्जा का त्रिपक्षीय सोपान

भारत का परमाणु मार्ग तीन अत्यंत जटिल चरणों से होकर गुजरता है:

1. **प्रथम चरण:** 'प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर' में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर ऊर्जा और उप-उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम-239 प्राप्त करना।
2. **द्वितीय चरण:** प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) में करना। यहाँ चमत्कार यह होता है कि रिएक्टर अपनी खपत से अधिक ईंधन (प्लूटोनियम) पैदा करता है और साथ ही थोरियम को विखंडनीय यूरेनियम-233 में परिवर्तित करता है।
3. **तृतीय चरण: पूर्णतः** थोरियम आधारित रिएक्टर, जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का अधिनायक बना देंगे।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर: अक्षय ऊर्जा का स्रोत

कलपक्कम का 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक (एमडब्ल्यूई) का यह रिएक्टर तकनीकी विशिष्टता का शिखर है। इसे 'भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड' (भाविनी) द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी 'ब्रीडिंग' क्षमता है - यह जलने के साथ-साथ नया ईंधन भी सृजित करता है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत रूस के पश्चात विश्व का दूसरा ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसके पास वाणिज्यिक स्तर का 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' कार्यरत है। यह 'मेक इन इंडिया' का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) का पसीना सम्मिलित है।

क्रिटिकैलिटी: परमाणु हृदय की धड़कन

विज्ञान की भाषा में 'क्रिटिकैलिटी' प्राप्त करने का अर्थ है वह बिंदु, जहां रिएक्टर के भीतर परमाणु विखंडन की श्रृंखला प्रतिक्रिया स्व-संचालित और स्थिर हो जाती है। अब इस रिएक्टर को बाहरी न्यूट्रॉन स्रोत की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसी सिम्फनी की भांति है, जहां नष्ट होने वाले और उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों के मध्य एक दिव्य संतुलन स्थापित हो चुका है। यह स्थिरता स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा का आधार है।

सुरक्षा और भविष्य की पदचाप

कलपक्कम का यह रिएक्टर सुरक्षा के अभेद्य मानकों से सुसज्जित है। किसी भी आकस्मिक विपत्ति की स्थिति में, यह तंत्र स्वतः ही निष्क्रिय होने की क्षमता रखता है। यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड ईंधन के चारों ओर यूरेनियम-238 की परत और भविष्य में थोरियम-232 का उपयोग भारत को 'ऊर्जा-अकाल' से सदैव के लिए मुक्त कर देगा।

नया भारत, नई शक्ति

अमेरिका और ईरान के मध्य जारी सामरिक संघर्षों के कोलाहल के बीच, भारत ने निःशब्द भाव से अपनी ऊर्जा सुरक्षा के दुर्ग को सुदृढ़ कर लिया है। कलपक्कम की यह सफलता केवल बिजली पैदा करने की मशीन मात्र नहीं है, बल्कि यह उस आत्मविश्वास का परिचायक है जो आधुनिक भारत की रगों में दौड़ रहा है। हम अब उस मुहाने पर खड़े हैं, जहां से भारत का परमाणु सूर्योदय समूचे विश्व को अपनी वैज्ञानिक आभा से आलोकित करेगा। ●

बिहार में नया 'सम्राट'

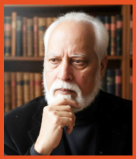

सच्चिदानंद

तीन दशकों तक लालू और नीतीश की धुरी पर घूमने वाली बिहार की सियासत अब एक ऐतिहासिक विस्थापन की साक्षी बनी है। भाजपा ने पहली बार मुख्यमंत्री पद पर अपना ध्वज फहराकर न केवल राज्य का राजनैतिक डीएनए बदल दिया है, बल्कि 2029 के महासमर की एक नई बिसात भी बिछा दी है।

> बिहार की राजनीति के 'भीष्म पितामह' नीतीश कुमार के दिल्ली प्रस्थान ने पटना के सत्ता-गलियारों में एक युग का अंत कर दिया है। अब सम्राट चौधरी के राज्याभिषेक के साथ बिहार, व्यक्ति-आधारित कूटनीति से निकलकर भाजपा के संरचनात्मक प्रभुत्व के नए युग में प्रवेश कर रहा है।

14 अप्रैल को राजनैतिक धूप में बिहार की माटी एक ऐसे परिवर्तन की साक्षी बनी, जिसने पटना के सत्ता-गलियारों में एक अनकही बेचैनी और अप्रत्याशित उत्साह का मिश्रण भर दिया है। बिहार की राजनीति के 'भीष्म पितामह' कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा की सीढ़ियों से राष्ट्रीय राजधानी 'इंद्रप्रस्थ' की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। यह कोई सामान्य स्थानांतरण नहीं है; यह उस अधि-वृतांत का समापन है, जिसने पिछले दो दशकों से बिहार की नियति को अपने कूटनीतिक कौशल से गढ़ा था। व्यक्तित्व-आधारित राजनीति के उस सूर्य का अब पाटलिपुत्र के क्षितिज पर सूर्यास्त हो रहा है, जिसकी धुरी पर राज्य के समस्त समीकरण घूमते थे। चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों या राष्ट्रीय जनता दल के साथ, सत्ता की बागडोर सदैव उनके ही हाथों में रही।

नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे रणनीतिकार की रही है, जो विपरीत धाराओं को भी अपने पक्ष में मोड़ने का सामर्थ्य रखते थे। किंतु आज, उनके दिल्ली प्रस्थान ने बिहार में जो नेतृत्व शून्यता उत्पन्न किया है, उसे भरने के लिए भाजपा ने अपने सबसे प्रखर योद्धा 'सम्राट चौधरी' को रणांगण में उतार दिया है। यह बदलाव केवल मुख्यमंत्री के चेहरे का परिवर्तन नहीं है, बल्कि बिहार के राजनैतिक चरित्र का 'हार्ड-रीसेट' है।

ऐतिहासिक उपलब्धि: कमल का पूर्ण उत्कर्ष

बिहार की सियासत में यह घटनाक्रम एक स्वर्णिम अध्याय की भांति है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तीन दशकों से अधिक समय तक बिहार की राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमती रही। भाजपा यहां सदैव एक सहयोगी की भूमिका में रही, एक ऐसी शक्ति जो सत्ता तक पहुंचाने का मार्ग तो प्रशस्त करती थी, किंतु स्वयं सिंहासन से वंचित रहती थी। इस प्रकार बिहार भारत का इकलौता हिंदी भाषी राज्य बना रहा, जहां भाजपा को कभी अपने दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त नहीं हुई थी।

सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जाना और उनका मुख्यमंत्री पद की ओर अग्रसर होना, उस 'कांच की छत' को तोड़ने जैसा है। वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान की घोषणा और विजय कुमार सिन्हा द्वारा उनके नाम का प्रस्ताव, भाजपा के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। यह उस 'चौथी जनरेशन' के सिपाही का उदय है, जिसने जमीन पर

मेहनत और बलिदान की लंबी यात्रा तय की है।

सम्राट चौधरी: विरासत और संघर्ष का संगम

सम्राट चौधरी भाजपा के उन नेताओं में से हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पारंपरकि पृष्ठभूमि से नहीं आते, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की उपज हैं। उनके पास एक समृद्ध राजनैतिक विरासत है। उनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे और कुशवाहा समाज के एक ऐसे कद्दावर नेता थे, जिनका प्रभाव सत्ता के गलियारों में सदैव बना रहा। शकुनी चौधरी ने नीतीश और लालू, दोनों के साथ सत्ता की साझीदारी की थी, और यही बहुआयामी राजनैतिक समझ सम्राट चौधरी को विरासत में मिली है।

1990 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने वाले सम्राट चौधरी का सफर

कांटों भरा रहा है। 1995 में राजनैतिक संघर्षों के कारण उन्हें 89 दिनों तक कारावास की यातना भी सहनी पड़ी। आरजेडी के टिकट पर परबत्ता से चुनाव जीतने से लेकर जदयू में नगर विकास मंत्री बनने तक, उन्होंने हर राजनैतिक घाट का पानी पिया है। 2017 में भाजपा में सम्मिलित होना उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। मार्च 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जिस आक्रामकता के साथ नीतीश कुमार के गढ़ में सेंध लगाई, उसी का परिणाम है कि आज वे बिहार के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं।

नीतीश का 'आशीर्वाद' और भाजपा की रणनीति

गिरिराज सिंह जैसे नेताओं का यह कहना कि 'नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिया है,' एक गहरे राजनैतिक संकेत की ओर इशारा करता है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना, एक सुनियोजित सत्ता-हस्तांतरण की रणनीति है। नीतीश ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे दिल्ली जाकर एक नई भूमिका निभाना चाहते हैं।

सम्राट चौधरी ने पदभार संभालने से पूर्व ही अपनी दिशा स्पष्ट कर दी है—'भाजपा की विचारधारा को श्रेष्ठ मानना और विकसित भारत के साथ समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करना।' नीतीश कुमार ने शासन चलाने की जो पाठशाला बिहार में स्थापित की थी, सम्राट अब उसे भाजपा के राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे के साथ समन्वित करने का प्रयास करेंगे।

संक्रमण की चुनौतियां और भविष्य का मानचित्र

बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां एक युग समाप्त हो रहा है और एक नई राजनैतिक संरचना जन्म ले रही है। नीतीश कुमार अब तक एक 'संतुलनकारी धुरी' थे, जो भाजपा और क्षेत्रीय अस्मिता के मध्य सेतु का कार्य करते थे। उनके हटते ही यह संतुलन खंडित हो सकता है। अब बिहार पूर्णतः भाजपा-प्रभुत्व वाले मॉडल की ओर बढ़ेगा।

विपक्ष, विशेषकर तेजस्वी यादव, इस बदलाव को 'दबाव का परिणाम' बता रहे हैं। उनके लिए यह एक अवसर भी है और चुनौती भी। यदि सम्राट चौधरी स्वयं को एक समावेशी और विकासोन्मुख मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने में सफल रहते हैं, तो विपक्ष के लिए 2029 की राह अत्यंत दुर्गम हो जाएगी। वहीं जदयू के भीतर अपने अस्तित्व को लेकर एक अनकही व्याकुलता है। नीतीश के पुत्र निशांत कुमार का राजनीति में प्रवेश इसी अस्तित्व की रक्षा का एक प्रयास माना जा रहा है।

पाटलिपुत्र का नव-जागरण

बिहार के राजनैतिक डीएनए में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सम्राट चौधरी का उदय केवल एक व्यक्ति का उत्थान नहीं, बल्कि बिहार की उस पिछड़ा और अति-पिछड़ा राजनीति के नए ध्रुवीकरण का प्रतीक है, जिसे भाजपा ने पिछले एक दशक में अत्यंत सूक्ष्मता से गढ़ा है। 20 वर्ष तक बिहार की गद्दी पर एक ही शहंशाह का राज रहा, किंतु आज विदाई की वेला में न कहीं शोक है, न उल्लास—केवल एक मौन प्रतीक्षा है।

बिहार अब उस ऊर्जावान नेतृत्व की बाट जोह रहा है, जो विकास के पायदान पर राज्य को अंतिम स्थान से निकालकर शीर्ष की ओर ले जाए। सम्राट चौधरी के सम्मुख चुनौती विशाल है, किंतु मगध का सिंहासन सदैव साहसी योद्धाओं का ही रहा है। इतिहास का पहिया घूम चुका है, अब देखना यह है कि 'नया सम्राट' बिहार की नियति का अगला अध्याय किस स्याही से लिखता है।●

आकाश की विवशता

गगन की अनंत सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले वायुसैनिकों का भविष्य आज तकनीकी विलंब और नीतिगत जड़ता के भंवर में फंसा है। स्वदेशी संकल्पों की विफलता ने भारतीय वायुसेना को पुराने प्लेटफॉर्मों और विदेशी निर्भरता की विवशता के कठोर धरातल पर ला खड़ा किया है।

संतु दास

किसी भी सैन्य शक्ति की सामर्थ्य केवल उसके अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों से नहीं, बल्कि उस नींव से मापी जाती है जिस पर उसके योद्धा निर्मित होते हैं। स्थिर और सुदृढ़ आधारभूत संरचनाएं विश्व भर की सेनाओं को रणनीतिक बढ़त प्रदान करती हैं। किंतु, भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के परिप्रेक्ष्य में, यह आधार आज जर्जर प्रतीत होता है। वायुसैनिकों के प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की गुणवत्ता और उनकी उपलब्धता में निरंतर गिरावट ने एक भयावह विद्रूपता उत्पन्न कर दी है। पिछले पांच दशकों में भारतीय आकाश ने जगुआर, मिराज-2000, सुखोई-30एमकेआई और राफेल जैसे अत्याधुनिक विदेशी विमानों की गर्जना तो सुनी, किंतु इन विमानों को उड़ाने वाले जांबाजों को प्रशिक्षित करने वाले स्वदेशी 'ट्रेनर' विमानों की कथा अत्यंत करुण और निराशाजनक रही है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पिस्टन इंजन से जेट तक का अधूरा स्वप्न

वायुसेना के प्रशिक्षण दर्शन का मूल सिद्धांत यह रहा है कि प्रत्येक प्रशिक्षु पायलट को एक मानकीकृत और त्रि-स्तरीय प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। इसमें टर्बोप्रॉप और जेट उड़ान का सघन अनुभव सम्मिलित है, जिसके पश्चात ही उसे फाइटर, परिवहन या हेलीकॉप्टर जैसे विशिष्ट संवर्गों के योग्य माना जाता है।

1960 के दशक के प्रारंभ से 2009 तक, यह यात्रा एचटी-2 और एचपीटी-32 जैसे स्वदेशी पिस्टन-इंजन विमानों पर टिकी थी। 1950 के दशक में निर्मित 'हिंदुस्तान ट्रेनर-2' ने तीन दशकों तक सेवा दी, जिसके पश्चात उसे एचपीटी-32 से प्रतिस्थापित किया गया। विडंबना यह थी कि एचपीटी-32 अपने जन्म के समय ही तकनीकी रूप से पुराना हो चुका था। टर्बोप्रॉप तकनीक की आवश्यकता को पूर्ण करने में अक्षम यह विमान दो दशकों तक रखरखाव की गंभीर समस्याओं और इंजन की अनिश्चितता से जूझता रहा।

2009: एक विभीषिका और रणनीतिक विवशता

वर्ष 2000 के पश्चात वायुसेना ने बार-बार सरकार को सचेत किया कि पिस्टन-इंजन वाले प्रशिक्षु विमान अब मृत्यु के जाल बन चुके हैं। उनकी मांग को तब गंभीरता से लिया गया जब एचपीटी-32 के इंजन की विफलता के कारण कई भीषण दुर्घटनाएं हुईं और राष्ट्र ने अपने अनमोल पायलटों को खो दिया। 2009 में इस विमान को अंततः सेवामुक्त कर दिया गया। किंतु, उस समय भारत के पास कोई स्वदेशी विकल्प उपलब्ध नहीं था। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के दावों के विपरीत, धरातल शून्य था। इस शून्य को भरने के लिए वायुसेना को विवश होकर अपने पुराने 'एचजेटी-16 किरण' जेट ट्रेनर को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त करना पड़ा - जो तकनीकी रूप से एक जोखिमपूर्ण कदम था।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 'सितारा' और 'यशस' जैसे विमानों पर अरबों रुपये व्यय होने के पश्चात भी उनकी प्रासंगिक प्रामाणिकता संदिग्ध है। प्रशिक्षण श्रृंखला की इस जर्जर कड़ी के कारण वायुसेना को अपने विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में जोखिमपूर्ण समझौते करने पड़ रहे हैं, जो अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

पिलाटस सौदा और एचएएल का अवरोध

2009 में वायुसेना ने 75 बुनियादी प्रशिक्षण विमानों के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदा जारी की। 2011 में स्विस निर्मित 'पिलाटस पीसी-7' का चयन हुआ, जो समकालीन और आधुनिक टर्बोप्रॉप तकनीक से सुसज्जित था। इस सौदे में 38 अतिरिक्त विमान खरीदने का विकल्प भी सम्मिलित था।

यहीं से स्वदेशी राजनीति और रणनीतिक यथार्थ का द्वंद्व प्रारंभ हुआ। एचएएल ने रक्षा मंत्रालय को इस सौदे को रोकने का परामर्श दिया और स्वयं के वित्तपोषण से 'एचटीटी-40' विकसित करने का प्रस्ताव रखा। वायुसेना का संदेह न्यायसंगत था, क्योंकि 1999 से एचएएल 'एचजेटी-36 सितारा' (इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर) के विकास में निरंतर विफल रहा था। जिस संस्थान ने एक दशक से अधिक समय में एक इंटरमीडिएट ट्रेनर नहीं दिया, वह तीन-चार वर्षों में बुनियादी ट्रेनर कैसे प्रदान करेगा? इसी अविश्वास के कारण वायुसेना ने 75 पिलाटस विमानों की खरीद को प्राथमिकता दी।

किंतु, एचएएल के अवरोध और नीतिगत संशय के कारण वायुसेना अतिरिक्त 38 पिलाटस विमानों के विकल्प का उपयोग नहीं कर सकी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि एचएएल द्वारा प्रस्तावित एचटीटी-40, जो पिलाटस का पूरक होना था, स्वयं देरी के कुहासे में विलीन हो गया। आज, एचएएल के वादे के एक दशक पश्चात भी यह प्लेटफॉर्म सेवा में पूरी तरह सक्रिय नहीं है।

मौजूदा संकट: किरण और हॉक के बीच की दरार

हिंदुस्तान जेट ट्रेनर-16 (किरण) की कहानी भारतीय उड्डयन के संघर्ष का प्रतीक है। यह 1950 के दशक के 'जेट प्रोवोस्ट' का लाइसेंस प्राप्त संस्करण है, जिसे रॉयल एयर फोर्स ने 1993 में ही विसर्जित कर दिया था। भारत ने इसे 1968 में अंगीकार किया और पिछले 40 वर्षों से यह हमारी रीढ़ बना हुआ है। यद्यपि 2006 में 'हॉक' विमानों के आगमन से कुछ राहत मिली, किंतु किरण के उन्नत संस्करण आज भी फ्लाइंग अकादमियों में अंतिम सांसें ले रहे हैं।

1980 के दशक में 'एडवांस्ड जेट ट्रेनर' (एजेटी) की अनुपलब्धता ने वायुसेना को उस स्थिति में धकेला जहां नए पायलटों को सीधे किरण से जगुआर और मिग जैसे शक्तिशाली विमानों में भेजा गया। यह व्यवस्था न केवल जोखिमपूर्ण थी, बल्कि वायुसैनिकों के कौशल विकास के लिए भी अपर्याप्त थी। 2006 में ब्रिटिश 'हॉक' के आने से इस स्थिति में सुधार हुआ, किंतु बुनियादी और इंटरमीडिएट स्तर पर संकट यथावत रहा।

'सितारा' का अवसान और 'यशस' का संशय

वायुसेना के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती 'एचजेटी-16 किरण' को 'एचजेटी-36 सितारा' से प्रतिस्थापित करने की है। एचजेटी-36 के विकास पर 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वाहा करने के पश्चात भी इसकी प्रामाणिकता शून्य है। तकनीकी विसंगतियों और डिजाइन की त्रुटियों ने इसे एक 'असिद्ध' प्लेटफॉर्म बना दिया है। एचएएल द्वारा इसे 'यशस' का नया नाम देने और ग्लास कॉकपिट लगाने के उपरांत भी वायुसेना इसके प्रदर्शन को लेकर आशंकित है।

इस विफलता का कोलेटरल डैमेज (पार्श्व क्षति) यह है कि वायुसेना अब हेलीकॉप्टर और परिवहन पायलटों को सीधे बुनियादी पिलाटस ट्रेनर से 'चेतक' हेलीकॉप्टरों या 'डोर्नियर' विमानों पर भेज रही है। यह प्रशिक्षण श्रृंखला के उस 'इंटरमीडिएट' चरण की हत्या है, जो एक पायलट के मानसिक और तकनीकी विकास के लिए अनिवार्य होता है।

उत्तरदायित्व का प्रश्न

एचएएल निरंतर 'बदलती आवश्यकताओं' और 'लक्ष्य परिवर्तन' का तर्क देकर अपनी देरी को उचित ठहराने का प्रयास करता रहा है। किंतु सैन्य विमानन की मूल्य श्रृंखला में एक आधुनिक प्रशिक्षण विमान की अनुपलब्धता वायुसेना के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र (ईकोसिस्टम) को पंगु बना रही है। जब प्रशिक्षण के स्तर पर ही समझौता किया जाता है, तो उसका प्रभाव लड़ाकू स्क्वाड्रन की मारक क्षमता और सुरक्षा पर पड़ता है।

अर्जुन सुब्रमण्यम (सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल) का यह विश्लेषण हमें उस वास्तविकता से रूबरू कराता है जहां 'आत्मनिर्भर भारत' का नारा एचएएल की अकर्मण्यता और तकनीकी जड़ता के कारण धूमिल होता दिख रहा है। वायुसेना को आज कल के वादों की नहीं, बल्कि आज के विश्वसनीय प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता है। यदि स्वदेशी संस्थान इस चुनौती को स्वीकार करने में विफल रहते हैं, तो राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए पुनः विदेशी देहरियों पर मस्तक झुकाना होगा - जो संप्रभुता के लिए एक सुखद संकेत नहीं है। ●

आकाश से पाताल तक की नाटकीय पटकथा

अंबर के आलिंगन का महाअभ्यास

अनंत अंतरिक्ष की निःशब्द गहराइयों को लांघकर जब भारत का 'गगनयान' वापस लौटेगा, तो उसकी सफलता का श्रेय रॉकेट की शक्ति को नहीं, बल्कि उन रेशमी छतरियों को जाएगा जो मृत्यु और जीवन के बीच सुरक्षा का एक अभेद्य सेतु निर्मित करेंगी।

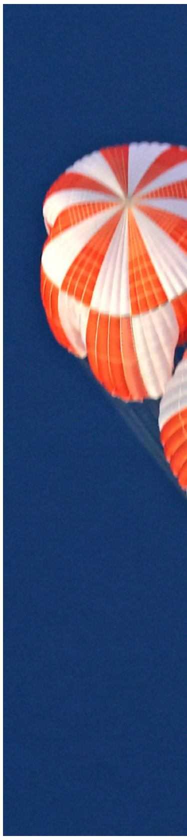

संदीप कुमार

कल्पना कीजिए, नीले आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर वायुसेना का एक 'चिनूक' हेलिकॉप्टर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ स्थिर है। उसके नीचे जंजीरों से जकड़ा हुआ एक भारी-भरकम पिंड - गगनयान का 'क्रू मॉड्यूल' - मानो अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक, वह जंजीर खुलती है। वह 4.8 टन का भारी धातु खंड गुरुत्वाकर्षण की प्रचंड शक्ति के साथ नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करता है। यह पतन नहीं है, यह एक सूक्ष्म गणना पर आधारित वह नृत्य है, जो तय करेगा कि जब भारत के वीर अंबर के आलिंगन से धरा की ओर लौटेंगे, तो उनकी वापसी एक गौरवशाली स्लैपडाउन (समुद्र में उतरना) होगी या एक भयावह त्रासदी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में अपने दूसरे 'इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट' (IADT-02) को सफलतापूर्वक संपन्न कर गगनयान मिशन की सफलता की इबारत में एक नया अध्याय लिख दिया है। यह परीक्षण उस 'अंतिम अंक' का पूर्वाभ्यास है, जिसे अंतरिक्ष यात्रा के सबसे खतरनाक चरण के रूप में जाना जाता है - पुनः प्रवेश और सुरक्षित लैंडिंग।

क्या है IADT-02 और इसकी सार्थकता?

अंतरिक्ष में जाना साहस का कार्य है, किंतु वहां से सुरक्षित लौटना परम विज्ञान है। गगनयान मिशन का मूल उद्देश्य तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और तीन दिनों के पश्चात उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। IADT-02 इसी 'सुरक्षित वापसी' की अग्निपरीक्षा है।

जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करता है, तो उसकी गति हजारों किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वायुमंडल का

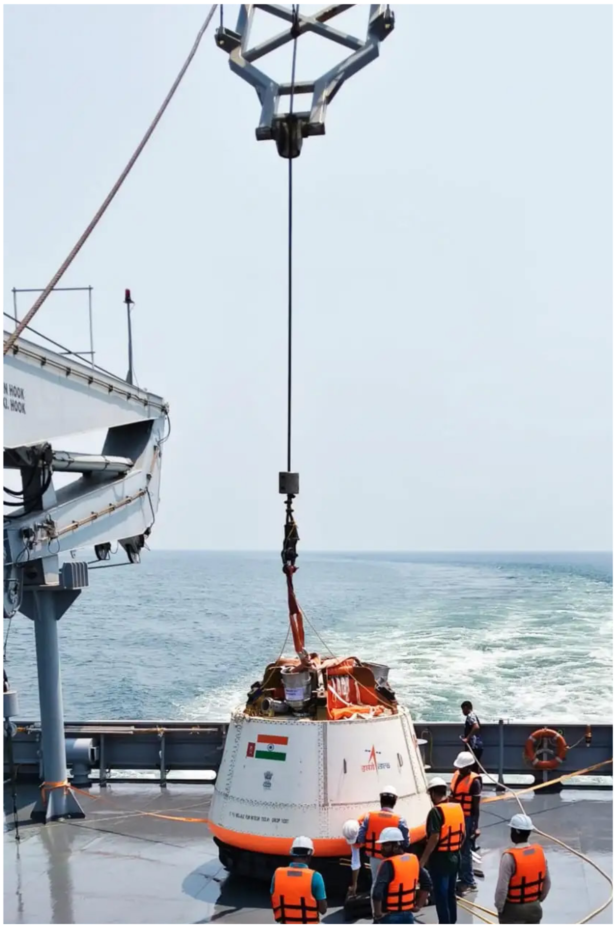

घर्षण उसे एक जलते हुए गोले में बदल सकता है। यहाँ 'हीट शील्ड' तो उसे जलने से बचाती है, किंतु समुद्र की सतह पर उतरने से पहले उसकी गति को इतना कम करना अनिवार्य है कि वह पानी से टकराते समय किसी पत्थर की तरह न टूटे। IADT-02 इसी अवतरण प्रक्रिया का एक सघन अनुकरण है।

पैराशूट: रेशमी सुरक्षा कवच का संगीत

IADT-02 की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसका पैराशूट तंत्र है। यह कोई सामान्य पैराशूट नहीं है, बल्कि यह प्रणालियों का एक जटिल समूह है जो एक निश्चित अनुक्रम में खुलते हैं। इसे आप 'गुरुत्वाकर्षण की सिम्फनी' कह सकते हैं।

इस परीक्षण में देखा गया कि कैसे 'एपेक्स' पैराशूट पहले खुलते हैं, जो मॉड्यूल को स्थिर करते हैं। इसके उपरांत 'ड्रोग' पैराशूट अपनी भूमिका निभाते हैं, जो गति को नियंत्रित कर उसे मुख्य पैराशूटों के खुलने योग्य बनाते हैं। अंत में, विशालकाय मुख्य पैराशूट खुलते हैं, जो उस भारी-भरकम मॉड्यूल की गति को मात्र 8 मीटर प्रति सेकंड तक सीमित कर देते हैं।

यदि इस अनुक्रम में एक सेकंड की भी त्रुटि हो जाए, या एक भी पैराशूट अपने पूर्ण विस्तार में विफल रहे, तो परिणाम आत्मघाती हो सकते हैं। इसीलिए इसरो बार-बार इन 'एयर ड्राप' परीक्षणों के माध्यम से तंत्र की विश्वसनीयता को प्रमाणित कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में एक बार की सफलता पर्याप्त नहीं होती; यहाँ हर बार पूर्णता की आवश्यकता होती है।

IADT-01 से IADT-02 तक का सफर

अगस्त 2025 में संपन्न हुआ प्रथम परीक्षण (IADT-01) इस मिशन की नींव था। उस समय इसरो ने पहली बार चिनूक हेलिकॉप्टर की सहायता से क्रू मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया था। उस परीक्षण ने हमें यह विश्वास दिलाया था कि हमारा पैराशूट तंत्र आपातकालीन परिस्थितियों में स्वतः सक्रिय होने की क्षमता रखता है।

द्वितीय परीक्षण (IADT-02) ने इस विश्वास को एक रणनीतिक गहराई प्रदान की है। इस बार विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों और 'असफलता की संभावनाओं' को ध्यान में रखकर परीक्षण किया गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि हमारा तंत्र न केवल आदर्श स्थितियों में, बल्कि चुनौतीपूर्ण और अप्रत्याशित मोड़ों पर भी अडिग रहेगा।

राष्ट्र की सम्मिलित शक्ति: इसरो, सेना और शोध संस्थान

गगनयान मात्र इसरो का स्वप्न नहीं है, यह समूचे राष्ट्र का संकल्प है। इस महापरियोजना में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) जीवन रक्षक प्रणालियों को गढ़ रहा है, तो भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट और चिनूक जैसे विमान इन परीक्षणों को आकाश प्रदान कर रहे हैं।

जैसे ही यह मॉड्यूल समुद्र की लहरों पर उतरता है, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की भूमिका प्रारंभ होती है। रिकवरी टीमों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कैसे वे न्यूनतम समय में मॉड्यूल तक पहुंचकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालें। यह समन्वय भारत की उस बढ़ती सामरिक शक्ति का परिचायक है, जहां जल, थल, नभ और अंतरिक्ष - सभी एक सूत्र में बंधे हैं।

अंबर के पथिकों की प्रतीक्षा

गगनयान की सफलता भारत को उन देशों की विशिष्ट श्रेणी में खड़ा कर देगी, जिन्होंने स्वयं के दम पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा है - अब तक यह गौरव केवल अमेरिका, रूस और चीन को प्राप्त है। एलवीएम3 (LVM3) रॉकेट, जिसे 'बाहुबली' की संज्ञा दी जाती है, इन अंतरिक्ष यात्रियों को अंबर के पार ले जाने के लिए तैयार खड़ा है।

किंतु, तकनीकी चमत्कारों से इतर, यह मिशन एक भावनात्मक यात्रा भी है। उन तीन भारतीयों के कंधों पर 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का भार होगा। IADT-02 जैसे परीक्षण हमें आश्वस्त करते हैं कि जब वे वीर 'गगन' से वापस लौटेंगे, तो धरा की गोद उनके स्वागत के लिए पूरी तरह सुरक्षित और सन्नद्ध होगी।

विज्ञान का नया महामंत्र

अंतरिक्ष अन्वेषण अब केवल जिज्ञासा का विषय नहीं रहा, यह भविष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। इसरो के वैज्ञानिक जिस सूक्ष्मता और समर्पण के साथ गगनयान के हर घटक को तराश रहे हैं, वह आधुनिक भारत की कर्मठता का प्रतीक है। IADT-02 की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब अंतरिक्ष की दौड़ में केवल एक सहभागी नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकारी शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है।

अगले वर्ष जब गगनयान का प्रक्षेपण होगा, तो समूचा विश्व भारत की ओर टकटकी लगाए देखेगा। तब हमें स्मरण होगा कि उस ऐतिहासिक सफलता की पटकथा इन्हीं 'वायु-बूंद' परीक्षणों के धुएं और पैराशूटों के रेशमी विस्तार में लिखी गई थी।

गगनयान केवल एक यान नहीं है, यह भारत के आकाश को छूने के अदम्य साहस का प्रतीक है। इसरो का यह पथ, सितारों के पथ से कम उज्ज्वल नहीं है। ●

अदृश्य आकाश, रक्तरंजित अरण्य

पूर्वोत्तर के अभेद्य जंगलों में अब बारूद की गंध के साथ एक अदृश्य तकनीकी जाल बिछाया जा रहा है। विदेशी हस्तक्षेप और ड्रोन-सैटेलाइट की जुगलबंदी ने पारंपरिक संघर्ष को अत्याधुनिक विभीषिका में बदल दिया है, जो भारत की सामरिक संप्रभुता के सम्मुख गंभीर चुनौती है।

हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा सात विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों में एक तीव्र स्पंदन पैदा कर दिया है। एक अमेरिकी और छह यूक्रेनी नागरिकों की यह संलिप्तता केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि भारत की अखंडता के विरुद्ध रचे जा रहे एक वैश्विक अधि-वृतांत का हिस्सा है। गैर-कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत की गई यह कार्रवाई उस सूक्ष्म तंत्र को उजागर करती है, जो यूरोप से अवैध ड्रोन मंगाकर उन्हें म्यांमार और मिजोरम के सशस्त्र विद्रोही समूहों तक पहुंचा रहा था। यह न केवल हथियारों की तस्करी है, बल्कि यह युद्ध के उस 'आउटसोर्सिंग' मॉडल का प्रमाण है, जहां तकनीकी प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सहायता सीमाओं को लांघकर भारत के दुर्गम अंचलों में प्रवेश कर रही है।

भारत की अरण्यानी (जंगल), चाहे वे उत्तर-पूर्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावन हों या तटीय दलदली क्षेत्र, सदैव से सैन्य अभियानों के लिए एक कठिन चुनौती रहे हैं। जैसे-जैसे भारतीय सशस्त्र बल 'एकीकृत थिएटर कमांड' (इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड) की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जंगलों में युद्ध का व्याकरण पूर्णतः बदल चुका है। अब यह लड़ाई केवल आमने-सामने की मुठभेड़ नहीं रही। इसमें दो प्रमुख मोर्चे हैं: प्रथम, पारंपरिक सेनाओं के मध्य सामंजस्य और द्वितीय, 'प्रॉक्सी' (छद्म) समूहों को मिल रही बाह्य तकनीकी शक्तियों का प्रतिकार। एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा जारी 'डिफेंस फोर्सेज विजन 47' इसी डिजिटल विभीषिका का सामना करने के लिए 'ड्रोन बल' की आवश्यकता पर बल देता है।

अतीत में जंगलों की सघन परतें (कैनोपी) निगरानी में सबसे बड़ी बाधा थीं, किंतु आधुनिक ड्रोन तकनीक ने इस अवरोध को एक सामरिक अवसर में बदल दिया है। सामान्य ड्रोन जहां जैमिंग (जैमिंग) और नेटवर्क के अभाव में पंगु हो जाते थे, वहां अब 'टेदर्ड ड्रोन' (केबल से जुड़े ड्रोन) एक अचूक समाधान बनकर उभरे हैं। ये ड्रोन केबल के माध्यम से निरंतर ऊर्जा और अटूट सिग्नल प्राप्त करते हैं, जिससे वे 24 घंटे से अधिक समय तक स्थिर रहकर सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि पर दृष्टि रख सकते हैं।

भारतीय सेना अब 'सॉफ्ट-किल' और 'हार्ड-किल' प्रणालियों का एक सघन जाल बुन रही है। जहां 'सॉफ्ट-किल' विधियों में सैटेलाइट नेविगेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी को स्पूफ (स्पूफ) करना शामिल है, वहीं 'हार्ड-किल' तकनीक में 30 से 300 किलोवाट तक के 'डायरेक्टेड-एनर्जी' हथियार (लेजर गन) तैनात किए जा रहे हैं। सक्षम, आकाशतीर और डी-4 जैसे सिस्टम अब रडार, थर्मल इमेजिंग और इन्फ्रारेड ट्रैकिंग के संगम से एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर रहे हैं, जिसे पार करना किसी भी 'स्वॉर्म ड्रोन' (ड्रोन झुंड) के लिए असंभव होगा।

पूर्वोत्तर के जंगल अब मौन नहीं हैं; वे डिजिटल तरंगों से स्पंदित हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जहां शत्रु अदृश्य है और अस्त्र डिजिटल हैं। भारत के ड्रोन बलों और थिएटर कमांड्स को अब एक ऐसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना होगा जहां तकनीक ही ढाल है और डेटा ही तलवार। यदि हम इस उभरते 'पैनॉप्टिकॉन' को समय रहते नियंत्रित करने में विफल रहे, तो हमारे अभेद्य जंगल हमारे लिए ही एक पारदर्शी युद्धक्षेत्र बन जाएंगे। ●

कृति का गेम चेंज!

हीरोइन या 'लेडी बॉस'

बॉलीवुड की चमकती दुनिया में कृति सेनन अब सिर्फ कैमरे के सामने मुस्कुराने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं—वह अब कैमरे के पीछे का खेल भी अपने हाथ में लेने के मूड में हैं। खबरें गरमा रही हैं कि कृति अपने प्रोडक्शन बैनर को फुल स्पीड में आगे बढ़ा रही हैं और अब उनकी नजर सिर्फ रोल्स पर नहीं, पूरी कहानी पर है।

सूत्रों की मानें तो कृति अब स्क्रिप्ट सुनते वक्त एक्ट्रेस कम, प्रोड्यूसर ज्यादा नजर आती हैं। नए चेहरे, हटकर विषय और कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा—यही उनका नया फॉर्मूला है। मतलब साफ है, कृति अब 'ग्लैमर गर्ल' के टैग से बाहर निकलकर इंडस्ट्री की 'डिसीजन मेकर' बनने की तैयारी में हैं।

दिलचस्प मोड़ यह है कि उनका यह कदम सिर्फ करियर शिफ्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा दांव है—जहां वह खुद अपनी फिल्मों की किस्मत लिखेंगी। बॉलीवुड में अब कृति का रोल बदल रहा है और यह बदलाव आने वाले समय में कई समीकरण हिला सकता है!

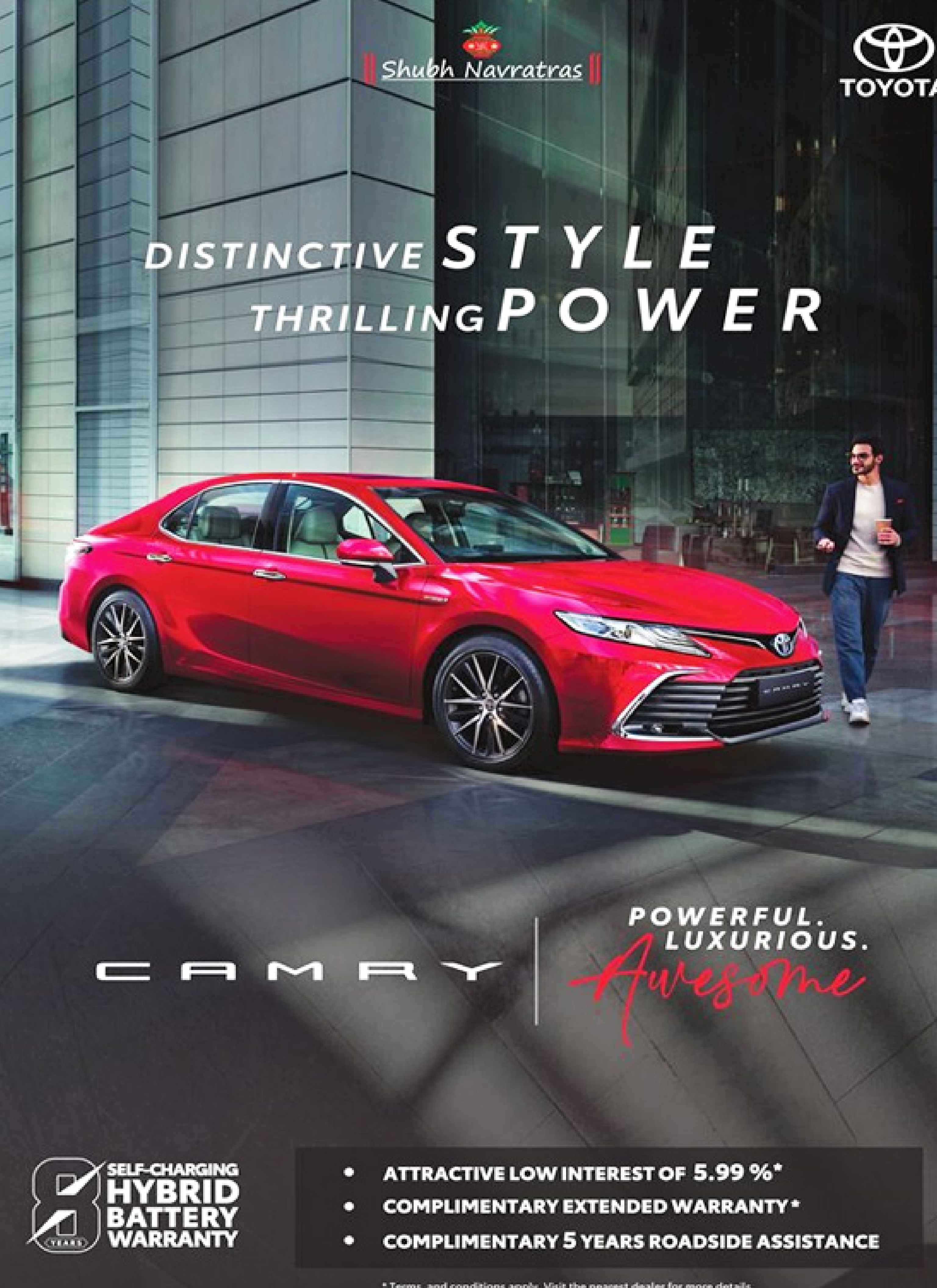

Shubh Navratras
TOYOTA
DISTINCTIVE STYLE
THRILLING POWER
CAMRY
POWERFUL.
LUXURIOUS.
Awesome
SELF-CHARGING
HYBRID
BATTERY
WARRANTY
YEARS
• ATTRACTIVE LOW INTEREST OF 5.99 %*
• COMPLIMENTARY EXTENDED WARRANTY*
• COMPLIMENTARY 5 YEARS ROADSIDE ASSISTANCE
* Terms and conditions apply. Visit the nearest dealer for more details.

PRGI NO : DELHIN/2017/74560